website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक रॉयल पत्रिका

वर्ष :13 | अंक : 275 | पेज: 8 | जयपुर, शुक्रवार 12 सितम्बर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आपदा का लिया जायजा

-1,200 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा

उत्तराखंड (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के हालात का जायजा लेने के लिए देहरादून का दौरा किया। हाल ही में आई भीषण बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। पीएम मोदी ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक विस्तृत बैठक की और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बच्चों ने इस आपदा में अपने माता-पिता खोए हैं, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पूरी सहायता दी जाएगी।

पीएम मोदी ने बताया कि राहत और पुनर्वास के लिए बहुआयामी कदम उठाए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ से मदद और पशुपालन के लिए मिनी किट का वितरण शामिल है।

उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवानों, राज्य प्रशासन और "आपदा मित्र" स्वयंसेवकों के काम की सराहना की और कहा कि राहत और बचाव कार्य में उनकी भूमिका बेहद सराहनीय रही है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 1,200 करोड़ रुपये की यह मदद आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत अंतरिम सहायता है। केंद्र सरकार आगे की जरूरतों का आकलन अंतर-मंत्रालयी टीमों और राज्य की रिपोर्ट के आधार पर करेगी और उसी हिसाब से अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करेगी और प्रभावित परिवारों व समुदायों को इस कठिन समय में हर संभव मदद देगी।

अमित शाह ने पांच नए हवाई अड्डों पर ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का किया शुभारंभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन–ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI–TTP) की शुरुआत की। इस सुविधा से यात्रियों को सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलेगा, जिससे लंबी कतारों और मैनुअल चेक से राहत मिलेगी।

यह प्रोग्राम भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों दोनों के लिए है। यात्री https://ftittp.mha.gov.in पोर्टल पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर e-Gates पर पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करने पर सिस्टम तुरंत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करता है और आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाता है।

बता दें कि FTI-TTP की शुरुआत 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी और बाद में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद में लागू किया गया। अब पांच और हवाई अड्डों के जुड़ने के बाद यह सुविधा 13 एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। आने वाले समय में इसे नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट पर भी शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब तक करीब 3 लाख यात्री पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं, जिनमें से 2.65 लाख ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "Speed, Scale और Scope" की दृष्टि को आगे बढ़ाती है और इससे न केवल यात्री सुविधा बढ़ेगी बल्कि देश की इमिग्रेशन व्यवस्था भी और मजबूत होगी।

राजनाथ सिंह ने मुंबई से 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान का किया शुभारंभ

-दुनिया की पहली त्रि-सेवा महिला नौकायन परिक्रमा

नई दिल्ली(एजेंसी)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रवाना किया। यह दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है, जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना की केवल महिला अधिकारी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह अभियान नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की एकता, आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक सोच का प्रतीक है। उन्होंने इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन और इच्छाशक्ति की आध्यात्मिक साधना बताया।

यह अभियान 9 महीने का होगा, जिसमें 10 महिला अधिकारी भारतीय सेना द्वारा निर्मित 50 फीट लंबे इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल (IASV) त्रिवेणी पर करीब 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगी। यह दल पूर्वी मार्ग से निकलेगा और भूमध्य रेखा को दो बार पार करेगा। वहीं दुनिया के तीन बड़े केप लीउविन, हॉर्न और गुड होप से गुजरेगा। साथ ही दक्षिणी महासागर तथा ड्रेक पैसेज जैसी कठिन जलधाराओं को पार करेगा। इस दौरान टीम चार अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों फ्रेमेंटल (ऑस्ट्रेलिया), लिटिलटन (न्यूजीलैंड), पोर्ट स्टैनली (कनाडा) और केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) पर भी रुकेगी। अभियान मई 2026 में मुंबई लौटेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि IASV त्रिवेणी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और नवाचार पर भरोसा दिखाता है। उन्होंने कहा कि हर एक नौटिकल मील देश की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि दल की अंतरराष्ट्रीय बातचीत भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को भी दुनिया के सामने रखेगी।

इस 10 सदस्यीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर कर रही हैं और स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू मुख्य सहयोगी भूमिका में हैं। अन्य सदस्य- मेजर करमजीत कौर, मेजर ओमिता दलवी, कैप्टन प्राजक्ता पी निकम, कैप्टन दौली बुटोला, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसांई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरुवि जयराम और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी भी शामिल हैं।

दल ने पिछले तीन वर्षों में कड़े प्रशिक्षण पूरे किए हैं, जिसमें कई ऑफशोर अभियानों और इस वर्ष मुंबई से सेशेल्स तक की अंतरराष्ट्रीय यात्रा शामिल है, जिसने उनके इस वैश्विक अभियान के लिए तैयारियों को साबित किया। यह परिक्रमा वर्ल्ड सेलिंग स्पीड रिकॉर्ड काउंसिल (WSSRC) के नियमों के अनुसार होगी, जिसमें केवल पाल (सेलिंग) की मदद से 21,600 नॉटिकल मील से अधिक की यात्रा करनी होगी और नहर शॉर्टकट या इंजन का सहारा नहीं लिया जाएगा। यह दल राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर वैज्ञानिक शोध भी करेगा। इसमें समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक का अध्ययन, समुद्री जीवन का दस्तावेजीकरण और समुद्री स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता शामिल होगी।

राजनाथ सिंह ने भारतीय नाविकों की उपलब्धियों को याद किया, जैसे कैप्टन दिलीप डोंडे (पहली सोलो परिक्रमा, 2009-10), कमांडर अभिलाष टॉमी (पहली सोलो नॉन-स्टॉप परिक्रमा, 2012-13) और आईएनएसवी तारिणी पर महिलाओं की नविका सागर परिक्रमा। उन्होंने विश्वास जताया कि IASV त्रिवेणी एक नया वैश्विक मानक स्थापित करेगी और भारत की समुद्री यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी।

इस वर्चुअल फ्लैग-ऑफ समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थलसेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख तथा वेस्टर्न नेवल कमांड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने अंत में कहा-"अभियान के दौरान हमारी अधिकारी अनेक चुनौतियों का सामना करेंगी, लेकिन उनका संकल्प अंधकार को चीरकर निकलेगा। वे सुरक्षित लौटेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि भारतीय महिलाओं का साहस असीमित है।"

वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात

वाराणसी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व और चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में 15 आईपीएस अधिकारी, 50 गैजेटेड अफसर और करीब 5 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

पीएम के काफिले की निर्बाध आवाजाही हेतु शहर में बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन किए गए हैं

शहर के कई हिस्सों में बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री के काफिले की आवाजाही बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। इसके अलावा, शहर का माहौल उत्सव जैसा हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े-बड़े कट-आउट्स और पोस्टरों से पूरा बनारस पटा हुआ है।

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की जानकारी दी

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 15 आईपीएस, 50 गैजेटेड अफसर और 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन लागू है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

सीसीटीवी और ड्रोन से सभी रूटों की निगरानी हो रही है

उन्होंने आगे बताया कि एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से सभी रूटों की निगरानी हो रही है। वहीं, योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्रा 'दयालु' ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हमेशा ऐतिहासिक होता है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों के बीच काशी में द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह काशी के लिए गर्व की बात है कि इस वार्ता के लिए हमारे शहर को चुना गया है। शहर के सारे चौराहे दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और काशीवासी अपने प्रिय नेता के स्वागत को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता ताज होटल में होगी

जानकारी के मुताबिक, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच ताज होटल में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। वार्ता के बाद पीएम मोदी अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्थानीय लोगों से मुलाकात और विकास परियोजनाओं का जिक्र हो सकता है। इसके बाद, दोपहर 3 बजे पीएम मोदी पुलिस लाइन से बाबतपुर एयरपोर्ट लौटेंगे और वहां से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील वार्ता सही दिशा में- पीयूष गोयल

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर तक फाइनल हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं।

गोयल ने आगे कहा कि इस ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रियों को इस समझौते पर काम करने और इस साल नवंबर तक पहले चरण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। गोयल ने आगे कहा कि इस ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए, और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है और प्रगति हो रही है। साथ ही कहा कि इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं।

गोयल का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर ट्रंप और मोदी के बीच ट्रेड डील पर सकारात्मक संवाद हुआ

गोयल का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संवाद हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि वह दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से खुश हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं

ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले हफ्तों में अपने "बहुत अच्छे दोस्त" प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को अपना घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताया

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को अपना घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेड डील भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने में मदद करेगी और आश्वासन दिया कि दोनों टीमें चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। बाद में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को फिर से शेयर किया, जो दिखाता है कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों में सकारात्मक रुख बना हुआ है।

नई दिल्ली में वीआरडीएल कॉन्क्लेव-2025 का उद्घाटन हुआ

-अनुप्रिया पटेल बोलीं– स्वास्थ्य अनुसंधान में नए मानक गढ़ रहा है भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नॉस्टिक लेबोरेटरी (VRDL) कॉन्क्लेव-2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व स्तर पर नए मानक स्थापित कर रहा है।

अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और VRDL नेटवर्क की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान समाज की सेवा में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर के VRDLs महामारी और संक्रमणों से निपटने में "सुरक्षा के प्रहरी" की तरह खड़े रहे हैं और समय-समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस मौके पर उन्होंने इन-विट्रो डायग्नॉस्टिक्स (IVD) वेलिडेशन पोर्टल और वेलिडेशन प्रोटोकॉल्स का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और उद्योग-हितैषी बनाएगा, जिससे नए टेस्ट और तकनीक जल्दी और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध हो पाएंगे। अनुप्रिया पटेल ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र का निर्माण कर रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पहली बार 13 मंत्रालयों और विभागों को एक छतरी के नीचे लाया गया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब संक्रमणों के शुरुआती पता लगाने से लेकर स्वदेशी टेस्ट वेलिडेशन तक कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस कॉन्क्लेव ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को एक साझा मंच प्रदान किया है, जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत के स्वास्थ्य विजन को और मजबूत करेगा।

ऑटोमोबाइल उद्योग में जीएसटी सुधार से 'मेक इन इंडिया' को नई रफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत का ऑटो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, फाइनेंसिंग और रखरखाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज बनाने से ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, एमएसएमई की भागीदारी बढ़ेगी और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल मिलेगा।

छोटी कारों पर जीएसटी रेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचने की उम्मीद है

ये नीतिगत सुधार न केवल घरेलू मांग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, बल्कि एक आधुनिक, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की भी शुरुआत करेंगे। दो-पहिया वाहनों (350-सीसी तक की बाइक) और छोटी कारों पर जीएसटी रेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह, 1800-सीसी से कम ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए बसों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। परिवहन सेवाओं पर व्यापक प्रभाव से बचने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को भी बढ़ाया गया है और आवश्यकता अनुसार लागू किया गया है।

वाहनों की बढ़ती बिक्री से गुणक प्रभाव पैदा होगा, जो पूरी सप्लाई चेन में एमएसएमई को मजबूती प्रदान करेगा

जीएसटी रेट कम होने से मांग बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं और टायर, बैटरियां, कांच, स्टील, प्लास्टिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सहायक उद्योगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वाहनों की बढ़ती बिक्री से गुणक प्रभाव पैदा होगा, जो पूरी सप्लाई चेन में एमएसएमई को मजबूती प्रदान करेगा।

बढ़ती मांग से डीलरशिप, परिवहन सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट एमएसएमई में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

बढ़ती मांग से डीलरशिप, परिवहन सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट एमएसएमई में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जीएसटी रेट कम होने से चालक, मैकेनिक और छोटे सर्विस गैराज जैसी अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों भी बढ़ेंगी। क्रेडिट-आधारित वाहन खरीद से खुदरा ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा और अर्ध-शहरी भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री से केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की शिष्टाचार भेंट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री ने राजस्थान में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान लॉजिस्टिक हब के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, दिल्ली से जैसलमेर, उदयपुर से जोधपुर, बांसवाड़ा से दिल्ली एवं डूंगरपुर से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी सुविधा में विस्तार पर चर्चा हुई। शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को भी रेलवे सुविधा से जोड़ने को लेकर वैष्णव से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के कार्यों में गति लाने एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू और मलेरिया की स्थिति की समीक्षा की

-राज्यों को सतर्कता और जनजागरुकता बढ़ाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों द्वारा चलाए जा रहे रोकथाम उपायों की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि आने वाले महीनों में सभी राज्यों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक परामर्श (Advisory) जारी किया गया है। इसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे रोकथाम गतिविधियों को और गति दें तथा समुदाय में जागरूकता अभियान को प्राथमिकता से संचालित करें।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 20 दिनों के भीतर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने कार्ययोजना को तेज़ करें, विशेषकर शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में साफ-सफाई, फॉगिंग, स्रोत-नियंत्रण तथा जनजागरूकता अभियानों को सशक्त बनाया जाए।

भारत ने पिछले वर्षों में मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और देश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का है। वहीं, डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की भागीदारी और समुदाय की जागरूकता को निर्णायक बताया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी ताकि डेंगू और मलेरिया दोनों पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

लोकतंत्र में जन अपेक्षाएं पूरी करना हो सर्वोच्च प्राथमिकता

लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना हमेशा से सबसे बड़ी कसौटी रहा है। यह व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है जब नागरिकों को यह भरोसा हो कि उनके वोट से बनी सरकार उनकी समस्याओं को हल करेगी और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम उठाएगी। पड़ोसी देश नेपाल में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया, उसने यह साफ कर दिया कि अगर लोकतांत्रिक सरकार जनता की उम्मीदों से मुंह मोड़ ले तो असंतोष किस तरह विस्फोट का रूप ले सकता है। नेपाल में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हालात इस कदर बिगड़े कि संसद भवन से लेकर कई नेताओं के घर तक प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग में झुलस गए। नेपाल में शुरू हुआ यह आंदोलन अचानक नहीं था। सोशल मीडिया पर कुछ समय से नेताओं और उनके परिवारों की आलीशान जीवनशैली की तस्वीरें वायरल हो रही थीं। आम नागरिक यह देखकर आक्रोशित थे कि सत्ता में बैठे लोग अपने बच्चों को विशेष सुविधाएं और ऐशो-आराम दे रहे हैं, जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरतों के संकट से जूझ रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही यही है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, न कि सत्ता में बैठे वर्ग के व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने का माध्यम। लेकिन नेपाल के हालात इस सिद्धांत से बिल्कुल उलट नज़र आए। लोगों का गुस्सा इस वजह से भी भड़का कि नेपाल में लोकतंत्र को राजशाही के विकल्प के तौर पर अपनाया गया था। जनता को उम्मीद थी कि इस परिवर्तन से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और शासन ज्यादा पारदर्शी तथा जवाबदेह होगा। लेकिन विडंबना यह रही कि लोकतंत्र के इन वर्षों में न तो भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकी और न ही रोजगार और विकास के अवसरों में वृद्धि हुई। जनता की निराशा धीरे-धीरे नाराजगी में बदली और सोशल मीडिया के जरिये यह आंदोलन की शक्ल लेने लगा। इस बार के आंदोलन की खास बात यह रही कि इसमें सबसे अधिक भागीदारी युवाओं की थी। 13 से 28 वर्ष के आयुवर्ग के युवा और विद्यार्थी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। वे न सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई से परेशान थे बल्कि उन्हें यह भी लग रहा था कि सरकार उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसे युवाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना। यही कारण रहा कि आंदोलन को 'जेन जी प्रोटेस्ट' का नाम दिया गया, क्योंकि नई पीढ़ी डिजिटल माध्यम से ही अपनी असहमति और गुस्से को प्रकट कर रही थी। यह घटनाक्रम भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक सबक है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के भरोसे में होती है। अगर जनता को यह लगे कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं और व्यवस्था केवल विशेष वर्ग के फायदे के लिए काम कर रही है, तो असंतोष फूट पड़ना तय है। लोकतंत्र को केवल चुनाव जीतने का साधन नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की निरंतर प्रक्रिया बनाना होगा।

युवाओं का आक्रोश: भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान युवा सोशल मीडिया बैन करने से भड़क उठा

-नेपाल में जेन-जी आंदोलन के राजनीतिक आयाम

नेपाल, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश, इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक ओर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता को जकड़ रखा है, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को देशव्यापी जेन-जी आंदोलन की आंधी के आगे न केवल पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। यह आंदोलन अचानक से पैदा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि यह लंबे समय से सुलग रही उस नाराज़गी का विस्फोट था, जो नेपाल के युवाओं ने भ्रष्ट नेताओं, कमजोर सरकारों और असफल नीतियों के खिलाफ महसूस की। खासकर सोशल मीडिया पर लगे बैन ने आग में घी का काम किया। नेपाल का युवा वर्ग, जो आज के दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफार्मों से अपनी आवाज बुलंद करता है, उसे जब चुप कराने की कोशिश हुई, तो आंदोलन ने भयंकर रूप ले लिया।

जेन-जी आंदोलन का उदय

सोशल मीडिया बैन – चिंगारी से लपट: 8 सितंबर से शुरू हुआ आंदोलन एक साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था। सरकार ने युवाओं की बढ़ती आलोचना को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई। लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। जिन युवाओं को सरकार "गुमराह भीड़" कह रही थी, वही सड़कों पर उतर आए। युवाओं का मानना था कि सोशल मीडिया उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है। बेरोजगारी से परेशान युवक नौकरी की तलाश में सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग कर रहे थे। कलाकार, यूट्यूबर और डिजिटल उद्यमी अपनी रोज़ी-रोटी का साधन इसी माध्यम से कमा रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया बैन को सीधे रोटी और रोज़गार पर हमला माना गया।

आंदोलन की विशेषताएं

इस आंदोलन को मुख्यतः जेन-जी (1995 से 2010 के बीच जन्मी पीढ़ी) ने नेतृत्व दिया। आंदोलन डिजिटल एक्टिविज्म से शुरू हुआ और ग्राउंड प्रोटेस्ट में बदल गया। इसने जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को तोड़ दिया।

के.पी. शर्मा ओली का पतन

इस्तीफा और देश छोड़ना: आंदोलन ने जैसे-जैसे जोर पकड़ा, वैसे-वैसे ओली की कुर्सी हिलती गई। अंततः उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि वे दुबई चले गए हैं।

चीन की कठपुतली छवि

ओली पर आरोप था कि वे चीन के हितों के हिसाब से नीतियां बनाते थे। भारत विरोधी नीतियां अपनाकर वे अक्सर दिल्ली से टकराव की स्थिति पैदा करते। नक्शा विवाद, व्यापारिक समझौते और सीमा पर तनाव इसी नीति का हिस्सा थे। लेकिन इस्तीफे के बाद भी वे चीन नहीं गए, जिससे यह सवाल खड़ा हुआ कि उनके और चीन के रिश्ते कितने मजबूती से टिके हुए थे।

नेपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि

राजशाही से लोकतंत्र तक: नेपाल में सदियों तक शाह राजवंश का शासन रहा। लेकिन 1990 के दशक से लोकतंत्र की मांग ने जोर पकड़ा। 1996 से शुरू हुआ माओवादी विद्रोह 10 साल तक चला। इसमें लगभग 16,000 लोग मारे गए और देश गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। 2006 में शांति समझौते के बाद माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आए।

2008 में राजशाही का अंत कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया।

माओवादियों की असफलता: जनता को उम्मीद थी कि माओवादी नेताओं से "नई नेपाल" की तस्वीर सामने आएगी।

लेकिन – सत्ता में आने के बाद वे भ्रष्टाचार और विलासिता में लिप्त हो गए। आम जनता को मिले सपने चकनाचूर हो गए। आर्थिक सुधार ठप पड़ गए और बेरोजगारी बढ़ती गई।

भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का संकट

नेपाल की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी आम बात है। बड़े ठेकेदार और नेता मिलकर योजनाओं का पैसा हड़प लेते हैं। विदेशी सहायता और लोन विकास में नहीं बल्कि नेताओं की तिजोरियों में चले जाते हैं। इसके साथ ही – बेरोजगारी ने युवाओं को हताश कर दिया। लाखों नेपाली नौजवान गल्फ देशों और भारत में मजदूरी करने को मजबूर हैं। जो पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए देश में अवसर नहीं हैं। यही कारण रहा कि युवाओं ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

नेपाल, भारत और चीन का त्रिकोण

नेपाल की राजनीति हमेशा से भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती रही है। ओली पर आरोप था कि उन्होंने भारत विरोधी एजेंडा पर काम किया और चीन के साथ अत्यधिक नजदीकी बढ़ाई। सीमा विवाद (लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा) को हवा दी। चीन से बुनियादी ढांचे के नाम पर कर्ज़ लिए, जो अब बोझ बनते जा रहे हैं। भारत के लिए नेपाल की स्थिरता अहम है, क्योंकि – भारत-नेपाल की खुली सीमा है। सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते गहरे हैं। नेपाल में अस्थिरता का असर सीधे भारत के उत्तराखंड, बिहार और यूपी पर पड़ता है।

श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति

नेपाल की स्थिति श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी होती जा रही थी। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ युवाओं ने विद्रोह किया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार विरोधी लहर चली। नेपाल में भी युवाओं का गुस्सा इतना प्रबल था कि उन्होंने ओली को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

राजशाही वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग

आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र बनने की मांग उठने लगी। बहुत से नेपाली मानते हैं कि राजशाही के दौर में देश स्थिर था। 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, लेकिन बड़ी आबादी आज भी खुद को हिंदू राष्ट्र मानती है। युवाओं के एक हिस्से को लगता है कि इससे देश की अस्मिता बचेगी और विदेशी हस्तक्षेप रुकेगा।

आंदोलन के सामाजिक आयाम

आंदोलन ने जातीय राजनीति को पीछे धकेल दिया। मधेसी, पहाड़ी, तराई – सभी समुदाय के युवा एकजुट हो गए। महिलाओं और छात्राओं की भी बड़ी भागीदारी रही। आंदोलन पूरी तरह युवा-केंद्रित रहा, जिसमें बुजुर्ग राजनेताओं की कोई जगह नहीं थी।

भारत के लिए संदेश

नेपाल की स्थिति भारत के लिए कई मायनों में चेतावनी है। यदि पड़ोस में अस्थिरता रहेगी तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। चीन इस मौके का फायदा उठाकर नेपाल में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत को चाहिए कि वह नेपाल के युवाओं के साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक और रोजगार संबंधों को मजबूत बनाए। नेपाल का जेन-जी आंदोलन केवल एक देश की राजनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि यह युवा शक्ति के उदय का प्रतीक है। सोशल मीडिया बैन करना सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आकर युवाओं ने सत्ता पलट दी। यह आंदोलन बताता है कि आज की पीढ़ी लोकतंत्र में केवल "मतदाता" बनकर नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनकर उभर रही है। नेपाल का भविष्य अब इस पर निर्भर करेगा कि वहां की नई राजनीति जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है या नहीं। यदि फिर वही पुरानी ग़लतियां दोहराई गईं तो आंदोलन की लपटें और भयंकर रूप ले सकती हैं।

लोकतंत्र और युवा अपेक्षाएं

नेपाल की मौजूदा परिस्थितियों ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मज़बूत नहीं होता, बल्कि उसकी असली मज़बूती जनता के विश्वास और युवाओं की भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि सरकार युवाओं को रोजगार, पारदर्शिता और अवसर नहीं देती, तो लोकतंत्र महज़ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। यही वजह रही कि जेन-जी आंदोलन ने लोकतंत्र के असली मायनों को सामने रख दिया। नेपाल का युवा वर्ग अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, वह निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया ने उन्हें यह ताकत दी है कि वे अपनी राय न केवल देश में बल्कि वैश्विक मंच पर भी दर्ज करा सकें। यही कारण है कि सोशल मीडिया बैन को उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला माना। आज नेपाल का उदाहरण पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि युवाओं की अनदेखी किसी भी सरकार के लिए घातक साबित हो सकती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज़ करके सिर्फ सत्ता से चिपके रहना लंबे समय तक संभव नहीं है।

चिंता: स्वच्छ जल और जागरूकता से ही टल सकती है बीमारियों की आशंका

-आपदा के बाद रोग नियंत्रण हम सबकी साझा जिम्मेदारी

भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में मानसून जीवन का अहम हिस्सा है। यह केवल खेती-बाड़ी और जलस्रोतों की ताज़गी का ज़रिया नहीं बल्कि कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन जाता है। बाढ़, जलभराव, टूटे-फूटे नाले, अव्यवस्थित शहरी ढाँचा और सफ़ाई की कमी मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि बीमारियों का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि हर साल मानसून के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में हज़ारों लोग जलजनित, मच्छरजनित और संक्रामक रोगों का शिकार हो जाते हैं। यह केवल स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है कि हम बीमारी के फैलाव को रोकें, जागरूकता बढ़ाएँ और स्वच्छ जल व स्वच्छता को प्राथमिकता दें।

आपदा के बाद स्वास्थ्य संकट क्यों?

प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ या भारी बारिश केवल मकानों और सड़कों को ही नुक़सान नहीं पहुँचातीं, बल्कि इनके बाद स्वास्थ्य आपदा का खतरा भी मंडराने लगता है। जलजनित रोग: गंदा पानी पीने से हैजा, डायरिया, टायफॉइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। मच्छरजनित रोग: जलभराव मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। संक्रामक रोग: भीड़भाड़ वाले राहत शिविरों में खसरा, फ्लू और स्किन इंफेक्शन जैसे रोग फैल जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य: आपदा के बाद तनाव, चिंता और अवसाद भी बढ़ जाते हैं, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है।

भारत में आपदा और बीमारियों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत के इतिहास में हर दशक में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है और उसके बाद महामारी जैसी स्थिति बनी है। 1934 बिहार भूकंप और बाढ़ के बाद हैजे ने हज़ारों लोगों की जान ली। 1978 में दिल्ली में बाढ़ आई तो डायरिया और मलेरिया ने बड़ा संकट पैदा किया। 2008 में कोसी नदी की बाढ़ से बिहार के लाखों लोग प्रभावित हुए और राहत शिविरों में संक्रामक रोग फैल गए। हाल ही में असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में बाढ़ के बाद डेंगू और मलेरिया के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। ये उदाहरण बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा के बाद बीमारी का प्रकोप कोई अपवाद नहीं बल्कि लगभग निश्चित परिणाम होता है।

स्वास्थ्य संकट: केवल चिकित्सकीय नहीं, सामाजिक चुनौती

अक्सर लोग समझते हैं कि आपदा के बाद बीमारियों का इलाज सिर्फ़ डॉक्टरों और अस्पतालों का काम है। लेकिन सच यह है कि यह सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती भी है। जब हज़ारों लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों की क्षमता कम पड़ जाती है। दवाओं, साफ़ पानी और खाने-पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है। गरीब और मज़दूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उनके पास इलाज और स्वच्छता के संसाधन नहीं होते। बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे जल्दी शिकार बनते हैं। इसलिए आपदा के बाद स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए केवल डॉक्टरों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रशासन, समाज और हर नागरिक को मिलकर काम करना पड़ता है।

रोग नियंत्रण में स्वच्छ जल की भूमिका

कहा गया है – "जल ही जीवन है" – लेकिन यही जल अगर गंदा और दूषित हो जाए तो मौत का कारण भी बन सकता है। आपदा के बाद अक्सर नदियों, तालाबों और हैंडपंपों का पानी गंदगी से भर जाता है। सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। राहत शिविरों में पानी की व्यवस्था ठीक न होने पर लोग संक्रमित पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं।

समाधान

उबालकर पानी पीना। क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल। पानी फिल्टर और RO यूनिट्स की व्यवस्था। सामुदायिक टैंकों और ट्यूबवेल की नियमित सफाई। स्वच्छ पानी सुनिश्चित करना महामारी को रोकने का सबसे पहला और कारगर कदम है।

टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ

आपदा के बाद सबसे अहम भूमिका टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की होती है। खसरा, हैजा और टायफॉइड जैसी बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीके ज़रूरी हैं। राहत शिविरों में मोबाइल हेल्थ यूनिट तैनात होनी चाहिए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को आपदा-प्रबंधन का प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी

आपदा-पूर्व तैयारी: मानसून शुरू होने से पहले ही मच्छरनाशी दवाओं का छिड़काव, नालियों की सफाई और टीकाकरण अभियान चलाना। आपदा के दौरान: राहत शिविरों में साफ पानी, भोजन और टॉयलेट की व्यवस्था। आपदा के बाद: प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाना और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति। जनजागरूकता अभियान: टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और स्थानीय अखबारों के माध्यम से लोगों को सावधानियाँ बताना।

समाज और नागरिकों की भूमिका

आपदा के समय केवल सरकार पर निर्भर रहना सही नहीं है। समाज और हर नागरिक की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं— अपने घर और मोहल्ले में पानी जमा न होने देना। बच्चों को उबला हुआ पानी और पका हुआ भोजन देना। बुखार, दस्त या उल्टी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। राहत शिविरों और सामुदायिक स्थानों पर सफाई बनाए रखना। स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन के साथ सहयोग करना।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ता खतरा

आज जब क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो आपदाओं और बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से मच्छरों का प्रजनन काल लंबा हो गया है। नई-नई बीमारियाँ उभर रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को आपदा-प्रबंधन नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।

आर्थिक बोझ और गरीबी का चक्र

आपदा के बाद बीमारियों का सबसे बड़ा असर गरीब और मज़दूर वर्ग पर पड़ता है। इलाज पर खर्च होने से उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। काम छूट जाने से रोज़गार खत्म हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कुपोषण और गरीबी का चक्र गहराता जाता है। यानी स्वास्थ्य संकट केवल मेडिकल समस्या नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्या भी है।

शैक्षिक सशक्तीकरण ही इस समाज को अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देगा

-जनजातीय शिक्षा का संकट: समान अवसरों की तलाश में एक पीढ़ी

भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन सभ्यता और सामाजिक बहुलता के लिए विश्वभर में जाना जाता है। यह देश 705 से अधिक अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes – ST) का घर है, जो जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये समुदाय मध्य भारत के जंगलों से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और राजस्थान के रेगिस्तानों तक फैले हुए हैं। इनके पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, विशिष्ट जीवनशैली और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है। लेकिन विडम्बना यह है कि भारत के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ये समुदाय आज भी शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरत से वंचित हैं। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक उत्थान, सशक्तिकरण और अवसरों की बराबरी का सबसे बड़ा साधन है। यदि किसी समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। यही स्थिति आज हमारे देश के अधिकांश जनजातीय समुदायों की है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में जनजातीय समुदायों की शिक्षा का इतिहास उपेक्षा और हाशिए पर रखे जाने की कहानी कहता है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों ने मुख्यधारा शिक्षा का जो ढांचा तैयार किया, उसमें आदिवासी समुदायों को लगभग नज़रअंदाज़ कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए— जैसे आरक्षण, विशेष योजनाएं, छात्रवृत्ति, एकलव्य विद्यालय आदि। इसके बावजूद जनजातीय शिक्षा का स्तर अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाया।

वर्तमान परिदृश्य और आँकड़े

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 59 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत था। इसका अर्थ यह है कि जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा से वंचित है। महिला साक्षरता दर जनजातीय समाज में और भी कम है, जिससे लैंगिक असमानता और गहरी हो जाती है। जनजातीय क्षेत्रों के बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। कई राज्यों में जनजातीय साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह स्थिति केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और विकासात्मक संकट को दर्शाती है।

जनजातीय शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां

भौगोलिक बाधाएं: जनजातीय क्षेत्र अक्सर घने जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में बसे होते हैं। इन इलाकों तक पक्की सड़क, बिजली, इंटरनेट और परिवहन की सुविधा नहीं पहुंच पाती। स्कूलों की दूरी अधिक होने से बच्चों का नियमित रूप से स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है।

आर्थिक विषमता: अधिकांश आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय परिवार उन्हें मजदूरी या घरेलू कामों में लगा देता है। पढ़ाई का ख़र्च (किताबें, यूनिफॉर्म, परिवहन) उनके लिए बोझ बन जाता है।

भाषाई और सांस्कृतिक अंतर

आदिवासी समुदायों की अपनी अलग भाषाएं और बोलियां हैं। मुख्यधारा की शिक्षा प्रायः हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में होती है, जिससे बच्चे प्रारंभ से ही पीछे रह जाते हैं। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति और जीवनशैली का समावेश न होने से वे शिक्षा से आत्मीयता महसूस नहीं कर पाते। शिक्षकों की कमी और उपस्थिति की समस्या दूरदराज़ इलाकों में योग्य शिक्षक जाना नहीं चाहते। जो शिक्षक नियुक्त होते हैं, वे भी नियमित रूप से स्कूलों में

उपस्थित नहीं रहते। शिक्षक और छात्रों के बीच भाषा व संस्कृति का फासला सीखने की प्रक्रिया को और कठिन बना देता है।

अवसंरचना की कमी: कई जनजातीय स्कूलों में भवन जर्जर हैं, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा नहीं है। डिजिटल शिक्षा की बात तो दूर, बिजली तक का अभाव है। इन कारणों से बच्चों और माता-पिता में शिक्षा के प्रति आकर्षण नहीं बन पाता।

सामाजिक उपेक्षा और भेदभाव: मुख्यधारा समाज में आज भी आदिवासी समुदायों को कमतर समझा जाता है। इससे आत्मसम्मान की भावना आहत होती है और शिक्षा के प्रति उनका विश्वास कमजोर पड़ता है।

सरकारी पहल और नीतियां

भारतीय सरकार और राज्य सरकारों ने जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): इन विद्यालयों का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में जहां जनजातीय आबादी 50% से अधिक है, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां: गरीब आदिवासी छात्रों की पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान (SSA): जनजातीय इलाकों में विशेष फोकस के साथ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मज़बूत बनाने की कोशिश। आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय: जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ रहने और खाने की सुविधा मिलती है। डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम: नई पीढ़ी को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास। फिर भी इन योजनाओं का असर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

सामाजिक संगठनों और स्थानीय पहल की भूमिका

सरकारी प्रयासों के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) और सामाजिक कार्यकर्ता भी जनजातीय शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती हैं। कहीं-कहीं पर 'मोबाइल स्कूल' और 'टेंट स्कूल' जैसी अवधारणाएं भी शुरू की गई हैं। महिला सशक्तिकरण पर फोकस कर, जनजातीय लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाकर शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है।

जनजातीय शिक्षा का सामाजिक-आर्थिक महत्व

गरीबी उन्मूलन: शिक्षा रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खोलती है। सामाजिक न्याय: शिक्षा से ही आदिवासी समुदाय मुख्यधारा समाज में बराबरी का स्थान पा सकते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण: जब शिक्षा में उनकी संस्कृति और भाषा का समावेश होगा, तभी उनकी पहचान सुरक्षित रह पाएगी। राजनीतिक भागीदारी: शिक्षित जनजातीय समुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सजग होकर हिस्सा ले सकेगा। स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधार: शिक्षित समाज स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर अधिक ध्यान देता है।

शहरी सेवा शिविर से नागरिक सुविधाओं में होगा विस्तार - भजनलाल शर्मा

-15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा राज्यव्यापी 'शहरी सेवा शिविर'

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

शिविर से संबंधित समग्र मार्गदर्शिका करें तैयार-

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

शहर होंगे स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित, सड़क और रोशनी की बेहतर व्यवस्था-

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण होगा। इसी तरह सड़कों की मरम्मत, सीसी और डामर सड़क पर पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के साथ ही अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अभियान में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भागीदारी रहेगी, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

नागरिकों को उपलब्ध होंगी त्वरित सेवाएं-

शिविर के तहत जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एन.ओ.सी., ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी एवं मोबाइल टावर एन.ओ.सी., ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना तथा यूडी टैक्स जमा करवाने की सुगम व्यवस्था की जाएगी।

आमजन तक पहुंचेगा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ-

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत की जाएगी। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे।

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब यह शिविर 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

शहरी सहकारी बैंक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य करें- राज्यपाल

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के शहरी बैंक समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने को अपना ध्येय बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यवसायी देशभर में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ सभी लोग सहकारिता से जुड़ें। इसी से राष्ट्र और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के जरिए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने पर भी विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सहकारी बैंक कार्य करेंगे तभी सही मायने में सबका साथ सबका विकास को हम साकार कर पायेंगे।

राज्यपाल बागडे गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में सहकार भारती एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव बैंक न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि यह लाखों लोगों को, उनके परिवारों के लिए आजीविका का एक मजबूत स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि सहकार में अपने लिए नहीं सबके विकास की सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में सहकारिता से कृषि और डेयरी का जो विकास हुआ है, वह प्रेरित करने वाला है।

राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता से सभी का समान आर्थिक विकास, रोजगार जनन और सामूहिक विकास संभव है। उन्होंने राजस्थान में अधिकाधिक सहकारी बैंक स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्थान में सरस की सहकारी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि डेयरी के साथ अन्य उत्पादों का भी सहकारिता की सोच से प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने सहकारिता में भारत के तेजी से आगे बढ़ने की चर्चा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन में विश्वभर में हमारा देश पहले स्थान पर है। सहकारिता को प्रभावी गति देने से इस क्षेत्र के माध्यम से हम सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सहकारिता के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बड़ोदा में एक अर्ध-सहकारी कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद विखे पाटिल और धनंजयराव गाडगिळ ने 1949 में प्रवरा सहकारी चीनी कारखाना की स्थापना की।

नए आपराधिक कानूनों की सफल क्रियान्विति में राजस्थान बने देशभर में रोल मॉडल- मुख्य सचिव

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नए आपराधिक कानून देश की न्यायिक प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के साथ आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप राज्य में इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए और प्रदेश को देशभर में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अनुसंधान अधिकारियों को नए कानूनों के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी हो इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। साथ ही आमजन को भी नए कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाये जाएँ।

मुख्य सचिव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में गवाहों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य लेने, एफआईआर दर्ज करने और सम्मन जारी करने जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी तथा अनावश्यक समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की स्थापना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, पुलिस स्टेशनों पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा, पर्याप्त मानव संसाधनों की नियुक्ति तथा आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नए कानूनों के तहत अनुसंधान एवं प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए जिलास्तरीय अधिकारियों को नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए और क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समय पर समाधान करना चाहिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कानूनों की बेहतर और प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कॉलोनाइजर द्वारा ली गई जमीन के मामले में चल रहे विवाद को लेकर प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। खोरा ग्राम पंचायत में भैरू बाबा मंदिर के पास एक कॉलोनाइजर द्वारा ली गई जमीन के मामले में चल रहे विवाद को लेकर गुरुवार को नायब तहसीलदार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजस्व मंडल की टीम के साथ ग्राम पंचायत सरपंच की मौजूदगी में जमीन का मौका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जमीन की नाप होने तक कार्य नहीं करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार जयपुर के एक प्रॉपर्टी व्यवसायी ने खोरा ग्राम पंचायत के टेक वाले भैरू बाबा मंदिर के पास करीब 28 बीघा जमीन खरीदी है। जिसको लेने के बाद से ग्रामीण ग्रामीणों का कहना है की भैरव बाबा मंदिर सड़क के पास से होकर धोली भाट,भूतों वाले बड़ तक सैकड़ो वर्ष पुराना आम रास्ता है जिसे बंद किया जा रहा है यहां पर यहां काफी मात्रा में सिवायचक जमीन है। जिसको भी कॉलोनी में मिलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना नयन तहसीलदार मनोहरपुर को दी। जिसपर वे राजस्व मंडल की टीम व ग्राम पंचायत सरपंच ईश्वर लाल के साथ मौके पर पहुंचे और मौका स्थिति का जायजा लिया। जहां ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से जमीन की नाप जोक करवाने ओर आम रास्ता खुलवाने की मांग की। जिस पर नायब तहसीलदार ने शीघ्र ही जमीन की नाप जोक करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पटवारी प्रियंका जांगिड़,राजेंद्र गुर्जर,सरपंच ईश्वरलाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री की पहल पर पहली बार आयोजित होगा "घूमर फेस्टिवल- 2025"

- आगामी 15 नवंबर को होगा घूमर फेस्टिवल का दिव्य एवं भव्य आयोजन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने की। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को घूमर फेस्टिवल की समयबद्ध और प्रभावी तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ पुनीता सिंह ने बताया कि घूमर फेस्टिवल न केवल लोकसंस्कृति का उत्सव बनेगा बल्कि महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में विश्वकर्मा स्टेडियम, पोली ग्राउंड और महिला निकेतन कॉलेज ग्राउंड पर विचार किया जाएगा। प्रतिभागियों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15 सितम्बर से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी तथा पंजीकृत संस्थाओं को ₹500 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा फेस्टिवल का आधिकारिक गीत तैयार कराया जाएगा और 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा। उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन स्थल पर टेंट, लाइट, साउंड, सजावट और फोटो-वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग संभालेगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीएचईडी और जेवीएनएल द्वारा स्थल पर पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्थल पर फूड स्टॉल, स्मारिका शॉप्स, पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आयोजन की तैयारियों और समन्वय की निरंतर समीक्षा के लिए एक विशेष ज्यूरी का गठन किया जाएगा। वहीं, जिला कलक्टर ने सभी विभागों को आपसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि यह फेस्टिवल राजस्थान की धरोहर और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके।

अजमेर संभागीय आयुक्त ने जल भराव प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने गुरुवार को अजमेर जिले के बोराज तालाब की पाल टूटने से हुए जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वे स्वस्तिक नगर एवं आसपास की कॉलोनियों में पहुंचे और वहां के जल प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। संभागीय आयुक्त ने क्षतिग्रस्त आवासों को देखकर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बोराज तालाब की पाल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था की जाए तथा पाल की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने भोजन, पानी, दवा एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कहा कि किसी भी प्रभावित परिवार को आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाए। उन्होंने मुआवजा आवेदन के लिए लगाए गए सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्षति का नियमानुसार मूल्यांकन कर सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला, नगर निगम उपायुक्त अनीता चौधरी, तहसीलदार ओम सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर पालिका की बड़ी कारवाई: 97 आवारा पशु पकड़े

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। नगरपालिका क्षेत्र में आवारा पशुओं से परेशान लोगों की शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। निमडिया अलवर से बुलाई गई विशेष टीम ने अब तक करीब 97 आवारा पशुओं को पकड़कर धूलेश्वर कॉलेज परिसर में एकत्रित कर घासीपुरा स्थित नारायणदास गौशाला में छोड़ा है। इस दौरान नगरपालिका एसआई मोनू ने बताया कि टीम में 6 लोग कार्यरत हैं और जब तक पूरे पशु नहीं पकड़े जाते, यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान आवारा पशुओं ने गांधी चौक, वामन मोहल्ला और श्रीभगवान कॉलोनी सहित कई जगहों पर लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया।इस दौरान राधाकृष्ण हरितवाल और निरंजन शर्मा सहित कई लोग इनकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में अब भी करीब 50 से अधिक आवारा पशु घूम रहे हैं, जो कभी भी किसी हादसे का कारण बन सकते हैं। नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी का कहना "नगरपालिका क्षेत्र से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चल रहा है। टीम लगातार कार्य कर रही है और गौशाला में छोड़ा जा रहा है।ओर शेष बचे सभी पशुओं को भी जल्द पकड़ा जाएगा। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।"

विद्यार्थियों को आत्मरक्षा एवम् योग संबंधी जानकारी प्रदान की

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। ग्राम लोचूकाबास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को उपप्रधानाचार्य मनोज शर्मा के सानिध्य में अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के सदस्यों ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा व योग संबंधी जानकारी प्रदान की। गायत्री परिवार के बल्लूराम कुम्हार ने विद्यार्थियों को एवं स्टाफ को दुपट्टा एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया । इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति के संबंध में अनेकानेक जानकारियां प्रदान की। इसी क्रम में मनोहरपुर स्थित 11 विद्यालय एवं एक कॉलेज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की बहने कुमारी रिद्धिमा (एमबीबीएस सेकंड ईयर), कुमारी प्रज्ञा ,कुमारी सविता (एमबीबीएस फर्स्ट ईयर) कुमारी रवीना, कुमारी तनु पाटीदार, कुमारी दुर्गा ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा,योग प्राणायाम निरोग रहने संबंधी जानकारी प्रदान की।

उन्होंने गायत्री मंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गायत्री मंत्र वचन और लेखन से व्यक्ति के मस्तिष्क की बुद्धि में विकास होता है। इस कार्य में लालचंद शर्मा व्यवसायिक, कैलाश चंद्र संयोजक, कैलाश जलजला, राम सिंह दादरवाल, साधुराम यादव सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में सहयोग दिया।

बाबा की छत के लिए गुड़एज़ ने 5 लाख की घोषणा की

-बाबा बुर्हानुद्दीन के दीवाने रंजो गम से मुरझाया नहीं करते- गुड़एज़

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर के समाज सेवी मुहम्मद जाहिद गुड़एज़ ने कहा की ताला ग्राम की ऊँची डूँगरी पर विराजमान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत बुर्हानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला आलेह के दीवाने रंजो गम से मुरझाया नहीं करते है। यह शब्द गुड़एज़ ने ग्राम ताला में बाबा के उर्स में जायरीनों को सम्बोधित करते हुए कहे। गुड़एज़ ने कहा की इरादे रोज बनकर टूट जाते हैं ताला में वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं।

गुड़एज़ ने कहा यह वो दर है जहां पर बादशाहों व मंत्री से लेकर संतरी तक अपनी फरियाद लेकर आते रहते हैं और खुदा बाबा के आए हुए जायरीनों की लाज रखता है इसलिए तो लोग कहते हैं कि बाबा के दीवाने रंज ओ गम से मुरझाया नही करते हैं। उन्होंने बाबा की छत के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की समाज सेवी ज़ाकिर खान गुड़एज़ ने कहा कि हद तपे सो औलिया बे हद तपे सो पीर, हद बे हद तपे ताको नाम फकीर।

दरगाह के ख़ादिमों ने कहा कि बाबा के दरबार मे जो भी आता है वह खाली हाथ नही जाता है ख़ादिमों ने भारत देश की तरक़्क़ी के लिए दुआएं करवाई इससे पूर्व उनकी दस्तारबंदी की गई।

ताला के नदीम खान शेख व सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक खान शेख़ ने बताया कि इस अवसर पर उनके साथ मे आए हुए लोगो की भी दस्तारबंदी की गई।

हज़रत सय्यद ज़ुल्फ़िक़ार अली शाह रह. का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स परवान पर

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर जिले की आमेर तहसील की घाटी में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हज़रत सय्यद ज़ुल्फ़िक़ार अली शाह रह. का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स 10 सितम्बर 2025 बुद्धवार को मिलाद शरीफ से शुरू हुआ जो कि 12 सितम्बर 2025 को कूल की रस्म के साथ विधिवत सम्पन्न होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंग्रेजी तारीख 10 सितम्बर बुद्धवार व चाँद की तारीख 17 रबी उल अवल को सुबह झंडा फहराया गया इसी के साथ रंग बिरंगे कपड़ो में सज संवर कर विभिन्न प्रकार के वाहनों में सवार होकर जायरीनों के जत्थे आना शुरू हुए, रात को ईशा के बाद मिलाद शरिफ हुई जिसमे ख़ुदा के हुक्म व मोहम्मद (स.अ.व.स.) के तरीके पर चलने की बात कही गई।11 सितम्बर गुरुवार को राजस्थान की प्रसिद्ध कव्वाल पार्टियों के संग चादर का जुलूस निकला व बाबा के चादर पेश की गई। इसके बाद में सम्पूर्ण रात्रि तक राजस्थान की प्रसिद्ध कव्वाल पार्टियों के द्वारा बाबा की मान मनुहार की गई।

इसी प्रकार अंग्रेजी तारीख 12 सितम्बर शुक्रवार व चाँद की तारीख 19 रबी उल अवल को सुबह 10 बजे फ़ातेहा व कूल और लंगर होगा इसमे सामूहिक कव्वाल पार्टियों द्वारा बाबा की मान मनुहार करते हुए कूल की रस्म की अदायगी करेंगे इसी के साथ विधिवत रस्म ओ रिवाज के उर्स का समापन होगा। लंगर (पंगत प्रसादी) के दौरान अकीदतमंदों द्वारा लंगर खाया जाएगा।इसी दौरान गठजोड़ा, मुंडन व चादर चढ़ाने सहित आदि कार्यक्रम भी होंगे।

निगम ने 5 हजार 500 रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 7 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में गुरूवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में ईएसआईसी हॉस्पिटल, बालाजी मोड़, दुर्गापुरा कृषि केन्द्र टोंक रोड़, ढेहर के बालाजी स्टेशन के सामने, लता सर्किल से खातीपुरा बाजार तक, गोपालपुरा पुलिया से लक्ष्मी मन्दिर तक दोनों तरफ अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 5 हजार 500 रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 7 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में ईएसआईसी हॉस्पिटल, बालाजी मोड़, दुर्गापुरा कृषि केन्द्र टोंक रोड़, ढेहर के बालाजी स्टेशन के सामने, लता सर्किल से खातीपुरा बाजार तक, गोपालपुरा पुलिया से लक्ष्मी मन्दिर तक दोनों तरफ अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्यवाई के दौरान 7 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 5 हजार 500 रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए	
टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912
कचरा गाड़ी के लिए	
ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420
पुलिस की मदद के लिए	
साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181

पानी के लिए	
जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400
मेडिकल इमरजेंसी के लिए	
एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771
घायल पशुओं के लिए	
नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

सखी क्लब की किट्टी पार्टी सम्पन्न

बारां (रॉयल पत्रिका)। सखी क्लब अध्यक्ष उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख व सचिव श्रुति सिंघल ने बताया कि बुधवार 10 सितम्बर को एक निजी रेस्टोरेन्ट में कोषाध्यक्ष मधु शर्मा कि तरफ से किट्टी का आयोजन किया गया। सभी का रोली-चावल लगाकर स्वागत किया गया एवं किट केट से मुँह मीठा करवा गया साथ ही आगे के सेवा कार्यों की रूप रेखा तैयार की गई। सह सचिव त्रिशला जैन व सभापति ज्योति पारस ने बताया कि नागपुर, कानपुर, छत्तीसगढ़, कुल्लू मनाली प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, द्वितीय स्थान पर नीतू गुप्ता एवं तृतीय स्थान पर संतोष जैन रही। अगस्त माह में जिनका बर्थ डे निकला व सितम्बर माह में जिन सखियों का बर्थ डे है उनको क्राउन माला पहनाकर उनका बर्थडे मनाया गया। साधना जैन व श्वेता जैन ने बताया कि अठ्ठनी, चव्वनी रूपया और सरप्राईज गेम में ज्योति पारस विजेता रही। हाऊजी व गेम्स बहूरानी राशि द्वारा खिलाये गये जिसमें प्रथम हाऊस ममता नागर का हुआ। अर्ली बर्ड, शालिनी गुप्ता, अर्ली नाइन आशा गोयल, अर्ली ओके मधु गुप्ता रही। सभी ने पहले नाश्ता किया फिर स्नेहभोज का आनन्द लिया। इस दौरान सुनीता जैन, सोनिया अदलक्खा, प्रीति शर्मा, मंजू जैन, रानी जैन, प्रेरणा शर्मा आदि क्लब सदस्याएं उपस्थित रही। अन्त में मधू शर्मा द्वारा सभी को धन्यवाद दिया।

पुराने शहर में डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाने हेतु स्थाई लोक अदालत का आदेश

-उल्लंघन करने वालों के पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

शादाब अली

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। स्थाई लोक अदालत द्वारा पुराने शहर क्षेत्र में डीजे साउंड पर रोक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने जिला कलक्टर काना राम एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को आदेशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि पुराने शहर सवाई माधोपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तेज आवाज में साउंड सिस्टम का उपयोग न हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अधिवक्ता अब्दुल हासिब द्वारा प्रस्तुत याचिका में यह उल्लेखित किया गया था कि पुराने शहर के मकान अत्यंत प्राचीन एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने से कंपन उत्पन्न होते हैं, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, उच्च ध्वनि स्तर जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कारक भी है। स्थाई लोक अदालत के आदेशानुसार जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग क्षेत्रीय निगरानी को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे ताकि ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित हो। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सार्वजनिक शांति व सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अदालत एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में विशेष रूप से पुराने शहर सवाई माधोपुर में सघन निरीक्षण अभियान चलाकर आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

केसरियां बालम, आओ नी पधारों म्हारे देश

-नील ने खिलाया कमल, मयूर और भवई नृत्य पर झूमें दर्शक

बारां (रॉयल पत्रिका)। बुधवार की रात्रि डोल मेला रंगमंच पर आयोजित अजमेर की कमला क्रियेशन हाऊस के कार्यक्रम में कलाकारों ने श्रोताओ का स्वस्थ मनोरंजन किया। दर्शकों की अपार भीड़ के बीच कलाकारों ने देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के उपरान्त स्टार नाईट ने आकर्षक टाईटल म्यूजिक के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। गायक कलाकार पिन्टु भट्ट ने देवा ओ देवा-गणपति देवा.... के साथ गजानन की स्तुति की और मंगल भवन अमंगल हारी... जैसे भजनों से दर्शकों में भक्ति का संचार किया। कार्यक्रम के आर्कषण रहे एंकर नीलकमल ने पूरी एनर्जी के साथ दर्शकों को बांधे रखा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी पर किये उनके युगल अभिनय के बाद दर्शकों ने मंच पर आकर उन्हे मालाओं से लाद दिया। वहीं महावीर मेहता एण्ड पार्टी की कलाकार मोहिनी पायल, पिंकी, वैशाली ने राजस्थानी गीत पर आर्कषक मयूर नृत्य एवं पंजाबी गीतों पर सामूहिक नृत्य कर दर्शकों का स्वस्थ मनोरंजन किया एवं फिल्मी नगमे नींद हमारी पिया, तुमने चुराई... तथा बीच बजरियां जो तुने मेरी पकड़ी बईया... पर चित्रहार प्रस्तुत कर खूब वाह वाही लूटी। कॉमेडियन पन्या सेपट और उनकी साथी कलाकारा ने कार्यक्रम में हास्य का तड़का लगाते हुए दर्शकों को गुदगुदाया। कार्यक्रम के दौरान भवई नृत्य के महारथी महावीर ने सिर पर दो सलेण्डर और मटकियां रख संतुलित नृत्य कर दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। पत्रकारों के रूबरू होते हुए उन्होने बताया कि आगामी 18 सितम्बर को वें रशिया के विशाल मंच पर अपने इसी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगें। एंकर नीलकमल ने कई फिल्मी कलाकारों की आवाज की हुबहु मिमिक्री कर श्रौताओं को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। दर्शकों की मांग पर पुनः कुमार नील मंच पर आये और अपनें अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों में छा जाने में कामयाब रहे। कार्यक्रम की शुरूआत में सभी कलाकारों सहित राजेश यादव, प्रदीप कदम्ब, लोकेश यादव, पवन मेघवाल, गोविन्द यादव, उदय सिंह यादव, जितेन्द्र यादव, आनन्द यादव, कमलेश यादव कमल यादव, धनराज यादव, राजेन्द्र यादव, भवानी शंकर गोस्वामी, महेश यादव, कुलदीप मेघवाल, आकाश कटारा, हरविन्दर सिंह, बन्टी बैरवा, रिंकू सुमन, सुरेन्द्र सुमन, चैथमल सुमन गिर्राज नागर, दानमल मीणा आदि का उपसभापति नरेश गोयल, मेलाध्यक्ष प्रतिनिधि पुरूषोत्तम नागर, रोहित सक्सेना, अर्जुन यशवंत, प्रदीप विजयवर्गीय, लीलाधर नागर, प्रशान्त भारद्वाज, हरिश कुमार ने साफाबंदी, माल्यापर्ण कर पौधे और समृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया।

शिविर में विशेष योग्यजनों को मिले ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र व सहायक उपकरण

-मुख्यमंत्री के निर्देशन में विशेष योग्यजन को जिला कलक्टर ने स्वयं किया सहायक उपकरणों का वितरण, बढ़ाया हौंसला

बारां (रॉयल पत्रिका) । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में "सशक्त बारां प्रगति को शक्ति अभियान" के तहत् विशेष योग्यजनों को संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग, उपकरण योजना-2025 के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पंचायत समिति परिसर, बारां में शिविर आयोजित किया गया। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने विशेष योग्यजनों को सात ट्राईसाइकिल, सात मानसिक विमंदित किट एवं पांच श्रवण यंत्र प्रदान किए। इस अवसर पर बारां प्रधान मोरपाल सुमन, उपखण्ड अधिकारी विश्वजीत सिंह एवं विकास अधिकारी सुश्री श्वेता सहित अन्य मौजूद रहे। शिविर में विशेष योग्यजनों की आवश्यकता एवं पात्रतानुसार सहायतार्थ उपकरण वितरित किए गए। उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरों पर संतोष और खुशी झलक रही थी। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी शुभम नागर ने बताया कि बारां जिले के सभी 8 ब्लॉकों में पंचायत समिति स्तर पर 4 से 19 सितम्बर 2025 तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी शिविर 12 सितम्बर 2025 (शुक्रवार) को प्रातः 10 बजे पंचायत समिति किशनगंज में आयोजित किया जाएगा। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना सत्यापन, सुखद दाम्पत्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना एवं दिव्यांग सहायक अंग, उपकरणों का चिन्हीकरण आदि कार्य सम्पन्न किए जाएंगे। शिविरों में लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष योग्यजन अपने यूडीआई कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं, ताकि पात्रजन राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर ले सकें। यह पहल विशेष योग्यजनों के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो "सशक्त बारां प्रगति को शक्ति अभियान" को धरातल पर सार्थक बना रहा है। इस अवसर पर बीडीओ स्वेता पोरवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

बहती हुई रक्तधार से, आज के हालात लिखता हूं...

-देर रात तक चला स्थानीय कवि सम्मेलन

शब्बीर हुसैन

बारां (रॉयल पत्रिका)। मंगलवार की रात्रि डोल मेला रंगमंच पर स्थानीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया जिसमें कई नवोदित प्रतिभाओं ने काव्य पाठ किया। इस दौरान वीर, हास्य व श्रृंगार रस के कवियों को काव्य प्रेमियों ने इत्मीनान से सुना। सर्वप्रथम अंकिता पांचाल ने मां सरस्वती की वंदना की एवं सुनील शर्मा ने अपनी वीररस की कविता के साथ सम्मेलन की आधारशिला रखी। उन्होने- दिल में प्यार, आंखों में गुस्सा, कविता में अंगार लिखता हूं, मैं बहती हुई रक्तधार से, आज के हालात लिखता हूं.... से दर्शकों की वाहवाही लूटी। मेवाराम चैधरी ने वृक्षारोपण का संदेश देते हुए- कुछ लोग पेड़ काटने आये थे गांव में, धूप ज्यादा है- कह कर, बैठ गये उसी की छाव में.... जैसी मार्मिक कविता पढ़ी। युवा कवि पीयूष परिन्दा और ओमप्रकाश शास्त्री नें आज की राजनीति पर कविताओं के माध्यम से करारे व्यग्य किये। सुरेश चक्रधारी ने हास्य की बौछार कर कवि सम्मेलन को ऊचाईयां प्रदान की। राजेश तिरंगा ने- उस दिल को जला डालों चूल्हे में, जिसे तिरंगे से प्यार नही जैसी वीररस की कविता पढ़ी। सम्मेलन में डायमण्ड बनकर उभरे शायर रईस फैंजी और वाहीद बारानवी। फैंजी की गजल आईना टूटकर बिखर गया यूं, उठाया ना गया, इस तरह टूटा मेंरा दिल, फिर से बसाया ना गया..... दर्शकों के दिल में उतर गई। मंच संचालन बच्छराज राजस्थानी ने किया। उन्होने भी काव्य की हर एक विधा पर कवियों को आमंत्रित कर एक मिसाल कायम की। इसके अतिरिक्त रमण अजमेरा, छीतरलाल गांवडेल, मनोज मस्त, राजेश पंकज समेत कोई चार दर्जन से अधिक कवियों नें अपना काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के पूर्व सभी कवियों समेत अंजली भूमलिया के वार्ड से जयप्रकाश, ओमप्रकाश सुमन, बलराम सुमन, रामपाल सुमन, सुनील सुमन, बद्रीलाल सुमन, महावीर सुमन, मुन्ना पीटीआई, सुरेश टांक, सीता सोन के वार्ड से रामबाबू प्रजापति, ओमप्रकाश यादव, नन्दकिशोर चन्देल, राधेश्याम ऐरवाल, परमानन्द राठौर, फूलचन्द प्रजापति, राधेश्याम सुमन तथा पार्षद टीना गहलोत के वार्ड से राजेन्द्र गहलोत, पवन प्रजापति, रमेश बैरवा, मुकेश यादव, गौबरीलाल, सुरजा गुर्जर, पवन शर्मा का उपसभापति नरेश गोयल, मेला अध्यक्ष प्रतिनिधी पुरूषोत्तम नागर, प्रदीप विजयवर्गीय, नवीन सोन, अक्षय भूमलिया, अर्जुन यशवंत, आदि ने माल्यार्पण एवं साफाबंदी तथा स्मृति चिन्ह देकर कर स्वागत किया।

जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा व परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न

-वित्तीय समावेशन व बीमा योजनाओं में अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया सहित जिले के बैंक अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएमईजीपी, एनयूएलएम, एनआरएलएम, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एससी/एसटी पीओपी, बीआरयूपीवाई एवं स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय पोषण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से वित्तीय समावेशन शिविरों में बीमा योजनाओं पर फोकस कर आमजन को जागरूक करने तथा अटल पेंशन योजना, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध बनाकर किसानों, युवाओं और पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही प्रत्येक बैंक अधिकारी को प्रतिदिन पेंडिंग प्रवादों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने, दस्तावेज अपलोड करने तथा मौके पर जाकर समाधान कर आमजन की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। बैठक में वार्षिक साख योजना, ऋण-जमा अनुपात, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, जन सुरक्षा शिविरों, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कमजोर वर्गों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश :- बैठक में जिला कलक्टर ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 4463 करोड़ रुपये के वार्षिक साख योजना लक्ष्य के सापेक्ष दूसरी तिमाही तक 35.71 फीसदी ऋण वितरण की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला वर्ग को प्राथमिकता देते हुए पात्रता अनुसार अधिकाधिक ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं न्यायसंगत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों से समर्पित भाव से कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की अपील की और पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक प्रदीप कुमार ने जिले की बैंकिंग योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए आगामी लक्ष्यों को साझा किया। आरएसईटीआई निदेशक नीरज कुमार गोपालिया ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं क्रेडिट लिंक के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने का आग्रह किया।

जिला कलक्टर ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में समस्याओं का किया निस्तारण

-फसल खराबे का लिया जायजा, कन्या आवासीय विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता परखी, छात्राओं से आत्मीय संवाद

बारां (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गुरुवार को जिले के किशनगंज ब्लॉक के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं, फसल खराबे का जायजा, एसडीएम कार्यालय, कन्या आवासीय विद्यालय निरीक्षण सहित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई कर समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में आमजन से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण कर राहत प्रदान की। शेष प्रकरणों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने किशनगंज एसडीएम कार्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने पत्रावलियों के संधारण, कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टरों में किए जा रहे इंद्राज एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों की गहन जांच की। इस दौरान उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलक्टर ने किशनगंज स्थित राजकीय जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध खाद्य सामग्री की जांच की और छात्राओं के लिए बनाए गए भोजन को स्वयं ग्रहण कर उसकी गुणवत्ता परखी। साथ ही छात्राओं से आत्मीयता पूर्वक संवाद कर उनकी पढ़ाई, भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली। कलक्टर ने विद्यालय प्रशासन को बच्चों की बेहतर देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

फसल खराबे का जायजा-

निरीक्षण के क्रम में जिला कलक्टर अकोदिया, किशनगंज के पहुंचे, जहां उन्होंने मानसून सत्र 2025 में अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

आई एफ डब्ल्यू जे का 131वां राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में प्रारंभ

जोधपुर (रॉयल पत्रिका)। जोधपुर भारतीय पत्रकारों की आवाज बुलंद करने वाला संगठन आई एफ डब्ल्यू जे का 131वां दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर के रातानाडा स्थित माहेश्वरी भवन में प्रारंभ हो गया है। जिसमें समारोह के मुख्याअतिथि पूर्व महाराजा गजसिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह को प्रारंभ करवाया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार आयशा खानम विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह, महासचिव मनवीर आदि उपस्थित रही।

कांग्रेस सेवादल का जिलास्तरीय संगठन सर्जन शिविर सोनाणा खेतलाजी में

मोहम्मद यासीन

पाली (रॉयल पत्रिका)। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत एवं जॉन प्रभारी मोहन हटेला के निर्देशानुसार पाली जिला कांग्रेस सेवादल का जिला स्तरीय सगठन सर्जन तीन दिवसीय आवासीय सहयोगी प्रशिक्षण शिविर सोनाणा खेतलाजी जूनी धाम प्रागण मे आयोजित होगा जिसकी शुरुआत 13 सितम्बर को प्रातः ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया जाएगा। पाली जिला कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने बताया की पाली जिले के सभी ब्लॉकों से 500 से अधिक सेवादल कार्यकर्ता शिविर मे हिस्सा लेगे। चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 13,14,15 सितम्बर तीनो दिन अलग सत्र मे अतिथि के रूप मे राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेता गण शिरकत करेंगे इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिशक के रूप मे गुजरात सेवादल प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश सेवादल उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह अडवाना, पवन चौधरी हिमाचली, अशोक कुमार क्रांति कारी,सहित नेशनल एवं राज्य स्तर के प्रशिक्षक शिविर मे प्रशिक्षण देगे वहीं अलग अगल सत्र में प्रोफेसर शिविर को संबोधित करेंगे 15 सितम्बर को सम्मापन होगा।

तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों के सदस्यों की बैठक आयोजित

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर जिला रसद कार्यालय में तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिला रसद अधिकारी अंशु तिवाड़ी ने बताया कि बैठक में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य व सतर्कता समिति के सदस्यों को उनके कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य व सतर्कता समिति के सदस्यों को विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव-अप अभियान की सम्पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सदस्यों को गिव-अप अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपात्र उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। इसी के साथ सदस्यों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य दुकानों के अधिक से अधिक निरीक्षण करने के संबंध में प्रेरित किया गया।

ऋण जागरूकता एवं एक मुश्त समाधान शिविर 15 सितंबर को

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर अनुजा निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी देने हेतु एवं एक मुश्त समाधान योजना हेतु जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर भवन में 15 सितंबर, 2025 को शिविर आयोजित किया जाएगा। अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक नगेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनुजा निगम के ऋण पोर्टल को ऋण आवेदन हेतु प्रारम्भ किया जा चुका है। जिले में शिविर का आयोजन करके अधिक से अधिक इच्छुक व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करने हेतु ऑनलाईन ऋण आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। जागरूकता शिविर के साथ ही अनुजा निगम द्वारा लागू एक मुश्त समाधान योजना में ऋणियों से ऋण के ब्याज की राशि की छूट प्रदान करते हुए अतिदेय मूलधन की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ जिन लाभार्थियों ने एक मुश्त समाधान योजना में पूर्व में ही लाभ ले रखा है, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा साथ ही निगम द्वारा पूर्व में किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति ऋण के ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, जन—आधार कार्ड, जाति प्रमाण— पत्र, आय प्रमाण — पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक) सहित शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आईटीआई जोधपुर में रोजगार सहायता शिविर सफलतापूर्वक आयोजित

21 संस्थानों ने लिया भाग, 388 अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन 640 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने किया सहभाग

जोधपुर (रॉयल पत्रिका)। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर द्वारा एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जोधपुर में किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणपत लाल सुथार ने निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को तकनीकी योग्यता अर्जित कर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का लाभ अधिक से अधिक संख्या में उठाना चाहिए। संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनिल व्यास ने बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार हासिल करने की जानकारी दी। वहीं, लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत के महासचिव सुरेश विष्नोई ने स्टॉलों का अवलोकन कर अभ्यर्थियों को शिविर का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के जिला समन्वयक अर्जुन सुथार ने कौशल प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी दी। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जोधपुर के उपनिदेशक आनंद कुमार सुथार ने बताया कि इस शिविर में कुल 21 संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें एसआईएस सिक्यूरिटी नीमच, केमिकल एंड मिनरल्स इंडिया प्रा. लि., जोधपुर डिफेंस सिक्यूरिटी सर्विसेज नई दिल्ली, चेकमेट सर्विसेज जयपुर, ल्यूसिड कॉलाईड जोधपुर, जनरल इंजीनियरिंग कंपनी जोधपुर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम आदि प्रमुख रहे। इन संस्थानों ने रोजगार हेतु 349 एवं प्रशिक्षण हेतु 39 अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन किया। इस शिविर में लगभग 640 बेरोजगार युवाओं ने भागीदारी की। शिविर संचालन में आईटीआई जोधपुर के अरुण बोड़ा, श्यामसिंह सोढ़ा, चन्द्रप्रकाश काग एवं रोजगार कार्यालय के श्रीराम दाधीच, प्रेम सिंह, कुलभूषण, नवीन माथुर सहित टीम के सदस्यों का योगदान रहा।

नई सज-धज के साथ आकर्षित कर रहा है गंगानगर का सुखाड़िया सर्किल

-मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिला कलक्टर की सोच से हुआ सुखाड़िया सर्किल का नवीनीकरण

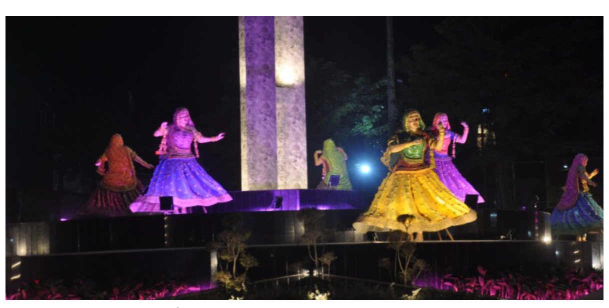

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार गत डेढ़ वर्षों से विकास कार्यों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के अलावा आमजन की छोटी परियोजनाओं पर भी गहनता से ध्यान दिया जा रहा है। आमजन को सुविधाएं मिलें, इसको लेकर सरकार गंभीर है। जिले में वृहद परियोजनाओं के अलावा सौन्दर्यकरण को लेकर भी जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में श्रीगंगानगर शहर के सुखाड़िया सर्किल की कायापलट की गई है। इसको सजाने व संवारने में जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शहरों को सुन्दर व स्वच्छ बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिला कलक्टर ने सुखाड़िया सर्किल की सजावट व सुगम यातायात बनाने के लिये योजना बनाई और नगर विकास न्यास सचिव अशोक असीजा के नेतृत्व में अधिकारियों को उसी के अनुरूप कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ ही महीनों के बाद अब सुखाड़िया सर्किल की छटा देखते ही बन रही है। इससे पूर्व सुखाड़िया सर्किल संकरा था, जिससे वाहन चालकों को आवागमन और यातायात व्यवस्था में असुविधा होती थी। आम नागरिक अपने वाहनों को लेकर निकलने में परेशानी महसूस कर रहे थे। ट्रेफिक लाइट लगाने के कार्य में भी सुखाड़िया सर्किल का संकरापन आड़े आ रहा था। जिला कलक्टर ने इस परेशानी से निजात दिलाने के लिये सुखाड़िया सर्किल का नया स्वरूप तैयार किया तथा नगर विकास न्यास द्वारा उसी के अनुसार कार्य किया गया। वर्तमान में सुखाड़िया सर्किल पर यातायात को सुव्यवस्थित करने वाली ट्रेफिक लाइट लगी हुई है, जिस कारण से नागरिक आसानी से सर्किल से आवागमन कर रहे हैं तथा नियमों की भी पालना हो रही है। सुखाड़िया सर्किल पर लगी रंग-बिरंगी लाइटें रात्रि के समय आने-जाने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इससे पहले सुखाड़िया सर्किल का ऐसा रूप देखने में नहीं आया। रंग-बिरंगी रोशनी में सजी-धजी विभिन्न मुद्राओं वाली राजस्थानी कलाकृतियां भी आमजन का मन मोह रही हैं। शाम के समय निकलने वाले नागरिकों को सुखाड़िया सर्किल की सुन्दरता आनन्दमय वातावरण प्रदान कर रही है। सुखाड़िया सर्किल पर शान से लहरा रहा तिरंगा भी इसकी सुन्दरता में चार-चांद लगा रहा है।

प्रशिक्षण में दी जन्म-मृत्यु एवं विवाह संशोधन की जानकारी

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला रजिस्ट्रार एवं उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी श्रीगंगानगर की तरफ से जन्म मृत्यु एवं विवाह के नवीनतम संशोधनों एवं नवीनतम प्रपत्रों की जानकारी के संबंध में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन पंचायत समिति हॉल सादुलशहर में किया गया। प्रशिक्षण ग्रामीण रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) समस्त ग्राम विकास अधिकारी सादुलशहर और शहरी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अधिकारी एवं कर्मचारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के जन्म-मृत्यु शाखा के अधिकारी व कर्मचारी के लिए जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एव उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी श्रीगंगानगर सरोज मूंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सरोज मूंड द्वारा सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 (संशोधन 2023) एवं राजस्थान जन्म-मृत्यु नियम 2000 (संशोधन 2025) में हुए संशोधनों से अवगत कराया गया। विकास अधिकारी सादुलशहर राजेन्द्र जोईया द्वारा जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के समस्त कार्य समय पर संपादित करने हेतु समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यालय उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी श्रीगंगानगर से आए मास्टर ट्रेनर सांख्यिकी निरीक्षक शिल्पा द्वारा उक्त संशोधनों के विषय में विस्तार से बताया गया एवं जन्म मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं का निराकरण किया गया। प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी विकास कुमार, संगणक संजीव कुमार, जिला स्तर से मास्टर ट्रेनर शिल्पा सांख्यिकी निरीक्षक, संगणक अनुपम कुमार एवं सहायक प्रोगामर दीपक उतरेजा आदि उपस्थित रहे।

मोबाईल वैन को एडीजे ने जिले में प्रचार-प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

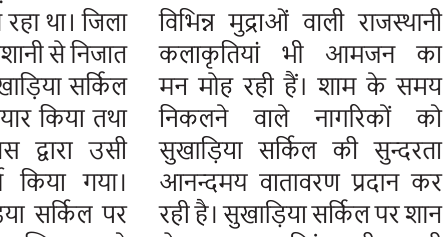

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर न्याय आपके द्वार की संकल्पना को सुनिश्चित करने के क्रम में सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं मोबाईल वैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में बुधवार को विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु आई। मोबाईल वैन के आगमन पर कर्मचारीगण, न्यायिक अधिकारी व अधिवक्तागण द्वारा मोबाईल वैन का स्वागत किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रवि प्रकाश सुथार द्वारा मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखाकर विधिक सेवा के प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार ने बताया कि यह मोबाईल वैन, सचल लोक अदालत, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं नालसा स्कीम की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न गाँव-गाँव व ढाणी-ढाणी में जाकर 10 सितम्बर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक आमजन को जागरूक करने का प्रयास करेगी। उक्त मोबाईल वैन को तालुका सादुलशहर में 10 अक्टूबर 2025 को अंतिम शिविर के पश्चात हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया जायेगा।

आदि कर्मयोगी-उत्तरदायी शासन अभियान

-3 दिवसीय जिला प्रोसेस लैब प्रशिक्षण प्रारंभ

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत आदि कर्मयोगी-उत्तरदायी शासन अभियान के तहत बूंदी जिला मुख्यालय स्थित एक निजी रिसोर्ट में जिला प्रमुख चन्द्रावती कंवर द्वारा बुधवार को 3 दिवसीय जिला प्रोसेस लैब प्रशिक्षण का दीप प्रज्ज्वलित कर प्रारंभ किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि जिले में जनजातीय विकास और परिवर्तन के लिए व्यक्तियों व संस्थाओं को सशक्त बनाने को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले की एक सौ ग्यारह ग्राम पंचायतों के 265 जनजातिय बाहुल्य क्षेत्रों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में 17 विभागों द्वारा विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जावेगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक मास्टर ट्रेनर (बीएमटी) को जिला मास्टर प्रशिक्षक (डीमएटी) द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर ब्लॉक मास्टर ट्रेनर द्वारा आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी व आदि साथी को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण उपरांत आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 17 विभागों की 25 योजनाओं से जनजाति समूह को लाभान्वित किया जावेगा। इस दौरान अधिशाषी अभियंता (इंजी.) प्रियवृत सिंह, लेखाधिकारी दीपक गौड़ सहित मास्टर ट्रेनर जिला सांख्यिकी अधिकारी सत्यवान शर्मा, अति. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) प्रहलाद शर्मा, आईसीडीएस विभाग के सीडीपीओ विपुल शुक्ला, डीपीएमयू विनीत शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

जिला परिषद की समीक्षा बैठक: अपूर्ण विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करें

-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर-2025 की तैयारियों पर दिया विशेष जोर

जोधपुर (रॉयल पत्रिका)। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा फलेगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए मण्डोर पंचायत समिति सभागार में जोधपुर एवं फलोदी जिले के पंचायत समिति विकास अधिकारियों एवं सहायक अभियंताओं की बैठक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिश्रा ने विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत एवं स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। साथ ही, पूर्ण हो चुके विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी 30 सितम्बर तक संबंधित शाखा प्रभारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी स्वीकृति संबंधी दस्तावेज चेकलिस्ट अनुसार भिजवाने पर जोर देते हुए पंचायत समिति मण्डोर, लूणी, चामू, बालेसर, धवा, कैरू, पीपाड़ शहर, बिलाड़ा, लोहावट, ओसियां एवं तिंवरी की वर्ष 2022-23 की अपूर्ण एवं धीमी प्रगति वाले कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने कहा कि मनरेगा एसएनए स्पर्श के माध्यम से भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वामित्व योजना पर विशेष निर्देश-

मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आउ, बिलाड़ा, फलोदी, वीरू और धवा के विकास अधिकारियों को लक्ष्य अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों के आवेदन-पत्र तैयार कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना पट्टा अभियान में प्रगति को लेकर कैरू, बापीणी, पीपाड़ एवं तिंवरी पंचायत समितियों को लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी और प्रॉपर्टी पार्सल अपलोडिंग कार्य में तेजी लाने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अटल ज्ञान केन्द्र कार्यों की समीक्षा-

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचायत समिति फलोदी में शहरी एवं ग्रामीण आवास कार्यों तथा कैरू, धवा, चामू एवं तिंवरी पंचायत समितियों के ग्रामीण आवास कार्य समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अटल ज्ञान केन्द्र के आवेदन-पत्र समय पर भेजने एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने को भी अनिवार्य बताया।

निवेशकों को समयबद्ध तरीके से नए कनेक्शन प्रदान किया जाना करें सुनिश्चित- जिला कलक्टर

धौलपुर (रॉयल पत्रिका)। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र, एकल खिड़की जिला सशक्त समिति एवं जिला निर्यात संवर्द्धन समिति की बैठक जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उद्यमियों को सुगम व्यापार का माहौल सुनिश्चित करने एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में नीतिगत प्रोत्साहनों पर उद्यमियों को सुगम माहौल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमोदन, अनुदानों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। उद्यमियों को सुगमता प्रदान करने हेतु सभी सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय करते हुए समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। जिले में निवेशकों को आने वाली समस्या के समाधान हेतु विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र समिति में जिला कलक्टर ने जेवीवीएनएल को निर्देश प्रदान किये कि निवेशकों को समयबद्ध तरीके से नये कनेक्शन प्रदान किए जाए। उन्होंने रीको ग्रोथ सेंटर क्षेत्र में स्थित इकाईयों, फीडर संख्या एक से सम्बन्धित उत्पादन इकाईयों की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। विद्युत में किसी प्रकार की ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। इकाईयों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि देवी सरस्वती आवरणशाला के लिए अस्थाई कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण रीको क्षेत्र में जलभराव की समस्या से सीलन के कारण आयरन कास्टिंग एवं इकाईयों उत्पादन समस्या को देखते हुए जल निकासी की समस्या का स्थाई समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण विक्रय का निरीक्षण करते हुए इकाइयों द्वारा प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए किए गए आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और उद्यमी भी साथ मिल कर जिले में सुगम व्यापार की संभावनाओं में सहयोग करें। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक मितुल गोयल ने उद्योगपतियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक रीको धौलपुर पिंतेश मीना, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल, उद्योगपति उपस्थित रहे।

अनुप्रति योजना के आवेदन 14 सितम्बर तक नि:शुल्क कोचिंग की मिलेगी सुविधा

अजमेर (रोयल पत्रिका)। विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए संचालित अनुप्रति योजना के आवेदन ऑनलाईन 14 सितम्बर तक भरे जा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फ्री कोंचिंग करने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 14.09.2025 निर्धारित की गई है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवाए जाने की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन एसएसओ आईडी पर सीएम अनुप्रति योजना के माध्यम से किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को योजना के लिए सत्र 2024-25 से लागू नवीनतम संशोधित दिशा निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार वांछित जानकारी सम्बन्धित दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन करें। राज ई वॉल्ट अथवा डिजी लॉकर में 10वीं एवं 12वीं की अंकतालिकाओं का डेटा अद्यतन करवाएं। योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन करते समय इन दस्तावेजों से संबंधित डेटा, योजना के पोर्टल पर ऑटो-फेज हो सकें।

खाद्य सुरक्षा का गेहूं ले रहे अपात्र व्यक्तियों को रसद विभाग ने दिए नोटिस

14,469 संभावित अपात्रों की सूची जारी

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए रसद विभाग ने पीलीबंगा तहसील के दुलवाना गांव में कई राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए हैं। विभागीय टीम ने पाया कि ये लोग अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेहूं का लाभ ले रहे थे। प्रवर्तन निरीक्षक पीलीबंगा पुरुषोत्तम भाटीवाल और प्रवर्तन निरीक्षक मनीष सिंगला ने गांव में जांच की। इस दौरान रामस्वरूप कुलडिया पुत्र साहब राम (अधिक कृषि भूमि), हरजीत पुत्र लाल सिंह (चौपाइयां वाहन धारक) और बादल सिंह (चौपाइयां वाहन धारक) को नोटिस दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि निश्चित अवधि तक संबंधित व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाते हैं, तो उनसे अब तक लिए गए समस्त गेहूं की एवज में 30.57 रुपए प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार विभाग लगातार ऐसे सभी कार्डधारकों को नोटिस दे रहा है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आमजन को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित करने हेतु चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अब तक पीलीबंगा तहसील में 9 हजार 972 लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा लिया है।

तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति एवं स्तरीय खाद्य सुरक्षा की बैठक आयोजित

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। बुधवार को जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी तथा प्रवर्तन निरीक्षक एवं सतर्कता समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) मोनिका जाखड़ द्वारा यह निर्देश दिए गए कि समिति के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के आसपास के खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों को चिह्नित कर राशन डीलर के माध्यम से गिवअप करवाएं। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) द्वारा बताया गया कि एनएफएसए में अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनसे गिव-अप अभियान के तहत आवेदन करवाए जा सके। एक नवम्बर से सभी अपात्र परिवारों से विभागीय नियमानुसार वसूली की जाएगी। जिले में 32 हजार 211 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए हैं। रमेश सिंह रावत सदस्य पीसांगन द्वारा सुझाव दिया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। जिले की उचित मूल्य की दुकानों की विज्ञप्ति के बारे में संक्षिप्त में बताया गया। तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति के सभी सदस्यों को जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों द्वारा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया।

बाल विवाह में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही- जिला कलक्टर

-बाल विवाह की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक सम्पन्न

जालोर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में मंगलवार को डीओआईटी सभागार में जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए आयोजित हो रही गतिविधियों के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते कहा कि अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों के अतिरिक्त अन्य विशेष सावों के दौरान अभियान चलाकर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन, सहयोगिनी सहित ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय रहकर कार्य करने के लिए पाबंद किये जाने की बात कही। जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी तथा बाल विवाह में सहयोग करने वाले एवं सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की जावें जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोकथाम लगाई जा सकें। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव कुमार सुथार ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए चाईल्ड हेल्पलाइन-1098, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल-181 कॉल सेन्टर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बरों पर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संबंधित पोर्टल पर आयोजित गतिविधियों को अपलोड करने एवं प्रचार-प्रसार किये जाने की बात कही। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा,, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भगवानाराम चौधरी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश कुमार मीना, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक अशोक विश्नोई सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा जिले के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

आशिकी ओटीटी के बाद अब बॉलीवुड डेब्यू करेंगे

रित्विक भौमिक

छोटे पर्दे और डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके अभिनेता रित्विक भौमिक अब सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रहे हैं। बंदिश बैंडिट्स के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले रित्विक जल्द ही अपनी पहली हिंदी फिल्म 'अभूतपूर्व' में नजर आएंगे। यह फिल्म रोमांटिक हॉरर कॉमेडी होगी, जिसकी कहानी 90 के दशक के आगरा की गलियों से शुरू होती है।

डिजिटल स्टार से फिल्मी हीरो तक

रित्विक भौमिक ने अमेजन प्राइम की म्यूजिकल वेब सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स' (2020) में राधे राठौर का किरदार निभाया, जिसके बाज उनकी पहचान बनी। इसके बाद रित्विक ने 'मजा मा' (2022) और 'खाकी: द बंगाल चैप्टर' (2023) जैसी प्रोजेक्ट्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब, फिल्मों में डेब्यू के साथ उनका करियर एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है।

'अभूतपूर्व' में खास किरदार

इस फिल्म में रित्विक 'अभय' नाम के युवक का रोल निभाएंगे। कहानी एक ऐसी मोहब्बत के इर्द-गिर्द घूमती है जो जिंदगी और मौत की बंदिशों के आगे बढ़ जाती है। आगरा के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण दिखाया जाएगा।

इंस्टाग्राम पर हुआ ऐलान

शनिवार को फिल्म से रित्विक का पहला लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। पोस्ट के साथ लिखा गया था कि यह कहानी एक ऐसी प्रेमकथा है जो अब तक न कही गई और न सुनी गई। यह झलक दर्शकों को फिल्म की दुनिया का अहसास कराने के लिए थी, जबकि पूरा सफर उन्हें सिनेमाघरों में दिखाई देगी।

फिल्म का प्रोडक्शन

फिल्म 'अभूतपूर्व' का निर्माण ख्याति मदान की कंपनी नॉट आउट एंटरटेनमेंट कर रही है। अभी फिल्म की बाकी कास्ट और टीम से जुड़े डीटेल्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह निश्चित है कि इसे बड़े पैमाने पर पेश किया जाएगा।

➤ पंचायत 5 का बेसब्री से

इंतजार कर रहीं हैं सानविका

प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत के अगले सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस साल जून में सीरीज का चौथा सीजन रिलीज हुआ अब दर्शक पंचायत 5 के इंतजार में हैं, जिसका एलान हो चुका है। दर्शक ही नहीं, पंचायत की रिंकी भी पांचवें सीजन का इंतजार कर रही हैं। हालिया पोस्ट के जरिए उन्होंने यह खुद कहा है। रिंकी का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस सानविका ने शुक्रवार को अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इसके साथ लिखा है, मैं पांचवें सीजन का इंतजार कर रही हूं उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए नेटिजन्स पूछ रहे हैं, पांचवां सीजन कब आएगा।

चाहे मैं बेसमेंट में रहूँ

मैं वफ़ादार रहूँगी

बोल्ड चॉइसेज़ और बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली कुब्रा सैत, जिन्होंने थिएट्रिकल और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिभा साबित की है, अब एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत कर रही हैं—अपने पहले रियलिटी शो राइज़ एंड फॉल के साथ। अपनी अनफ़िल्टर्ड पर्सनैलिटी और वर्सटिलिटी के लिए मशहूर एक्ट्रेस अब ऐसे मंच पर खुद को आज़मा रही हैं जहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही असली नियम है। कुब्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने इस सफर के मायने बताए। अपनी ईमानदारी और गहराई से भरे अंदाज़ में उन्होंने कहा-मुझे अनजाने को खोजने का शौक है और यह मेरे लिए सबसे बेहतरीन अनुभव होने वाला है। मेरी ज़िंदगी के अनुभवों के हिसाब से, मैं कभी शासक बन सकती हूँ तो कभी मेहनतकश इंसान। मैं एक भरोसेमंद, ज़िम्मेदार इंसान हूँ। चाहे मैं बेसमेंट में रहूँ, मैं वफ़ादार रहूँगी। और हम ज़रूर उठेंगे। उनका यह बयान बिल्कुल वही दर्शाता है जिसकी उम्मीद उनके फैंस उनसे करते हैं— हिम्मत, यक़ीन और अटूट जज़्बा। यह राइज़ एंड फॉल के फॉर्मेट को भी बखूबी दर्शाता है, जहाँ कंटेस्टेंट्स को ऊँचाइयों और गहराइयों से गुज़रते हुए, लॉयल्टी, स्ट्रैटेजी और एडैप्टेबिलिटी की असली परीक्षा देनी पड़ती है। यह मौका है स्क्रिप्ट्स और किरदारों को पीछे छोड़कर खुद को असली और अनफ़िल्टर्ड रूप में पेश करने का। उनके शब्द यह जताते हैं कि वह केवल सर्वाइव ही नहीं करना चाहतीं, बल्कि मुश्किलों के बावजूद मजबूती से खड़ी होकर जीतना चाहती हैं। राइज़ एंड फॉल के साथ, कुब्रा अपने शानदार करियर में एक और अध्याय जोड़ रही हैं। फिल्मों और वेब-शोज़ में अपने स्टैंडआउट परफ़ॉर्मेंस की तरह ही अब वह रियलिटी शो की अनिश्चित दुनिया में भी उतनी ही ऊर्जा के साथ कदम रख रही हैं।

जिया शंकर ने लाल साड़ी में बिखेरा जादू

बस उसी की बनकर वाले कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

टीवी से लेकर वेब सीरीज तक, जिया शंकर उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है। वह अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर को लाखों लोग पसंद करते हैं। मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर नया फोटोशूट पोस्ट किया, जिसने फैंस को फिर एक बार उनका दीवाना बना दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटोशूट में जिया शंकर ने रेड कलर की पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। साड़ी में हल्की चमक है। इस चमक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह रेशमी या साटन कपड़े की साड़ी हो सकती है। साड़ी के बॉर्डर पर बारीक कढ़ाई की गई है जो पूरे लुक को शाही बना रही है। साड़ी से ज्यादा ध्यान उनके ब्लाउज ने खींचा है। ब्लाउज पर सुंदर सी कढ़ाई हुई है और बाजुओं पर सफेद हंस का डिजाइन बना हुआ है। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है और सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किए हुए हैं, जो उनके चेहरे को और भी निखार रहे हैं। इस लुक पर उन्होंने मेकअप भी बहुत हल्का और सॉफ्ट रखा है। गुलाबी लिपस्टिक, हल्का आईशैडो और काजल के साथ उनकी मुस्कान दिल को छू रही है।

आशिकी 3 को लेकर मोहित सूरी ने तोड़ी चुप्पी

फिल्ममेकर मोहित सूरी ने हाल ही में बताया कि वो आशिकी 3 खुद डेवलप कर रहे थे, लेकिन खराब स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें इससे बाहर कर दिया गया। शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में सूरी ने कहा कि वह आशिकी 3 डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो ने फैसला किया कि वह उनके बिना आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया कि मैं स्क्रिप्ट को फाइन-ट्यून करूं। यह सच है कि उन्होंने हाल की फ्लॉप फिल्मों के आधार पर मुझे जज किया। यहां तक कि मेरे अपने परिवार वाले, जो डिसीजन में शामिल थे, इंतजार करने को तैयार नहीं थे। मैं उन्हें दोष नहीं देता, यह बिजनेस है, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करना नहीं चाहता था, मैं खुद को गलत साबित करना चाहता था।

आशिकी 2 का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म को टी-सीरीज फिल्म्स और विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था। आशिकी 2 का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म को टी-सीरीज फिल्म्स और विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था। मोहित ने मेंटल प्रेशर पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जब आप लो होते हैं तो किसी की मत सुनो, वर्ना और नीचे गिर जाओगे। बीस साल काम करने के बाद जब फिल्म फ्लॉप हो जाए तो डर लगता है कि अच्छा वक्त पीछे छूट गया है। लोग पहले ही ऐसा कहना शुरू कर चुके थे। मोहित सूरी ने माना कि बॉक्स ऑफिस हिट के पीछे भागते-भागते असली रास्ता छूट गया। उन्होंने कहा, एक विलेन 2 में मैं सिर्फ बॉक्स टिक कर रहा था, सीक्वल बना रहा था, गानों का रीमिक्स कर रहा था, कई लीड्स कास्ट कर रहा था। मैं 16 करोड़ की ओपनिंग दोहराना चाहता था, लेकिन गलत वजह से फिल्म बना रहा था। नतीजा सबके सामने है।

मोहित सूरी ने यह भी कहा कि आशिकी 3 और आवारापन 2 खोने के बाद भी उन्हें अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा, आशिकी मैं आदित्य और श्रद्धा के बिना कैसे बना सकता हूं? पहली फिल्म ने बड़ी ओपनिंग नहीं ली थी, लेकिन धीरे-धीरे कल्ट बन गई। आज ब्रांड नेम से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं अब उस जगह फिट बैठता हूं। फिलहाल यह प्रोजेक्ट अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें कार्तिक आर्यन और श्रीलीला नजर आएंगी। हालांकि, फिल्म को अब तक आधिकारिक तौर पर आशिकी 3 नाम नहीं दिया गया है।

साभार एजेंसी

अभिनेत्री ग्रेसी ने गुपचुप रचाई शादी

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री ग्रेस एंटनी ने अचानक अपनी शादी की तस्वीरें साझा कर सभी को हैरान कर दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटोज को शेयर किया है।

मलयालम एक्ट्रेस ग्रेस एंटनी ने अपने फैंस को तब बड़ा सरप्राइज दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अचानक अपनी शादी की तस्वीरें साझा कीं। फिल्मों में ग्लैमरस और दमदार किरदार निभाने वाली ग्रेस ने अपनी निजी जिंदगी का यह अहम फैसला बेहद सादगी और चुपचाप लिया। उन्होंने बिना किसी शोर-शराबे के सिंपल तरीके से शादी की। ग्रेस ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें पोस्ट कीं, उनमें वो दुल्हन के जोड़े में अपने पति का हाथ थामे नजर आ रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा - न कोई आवाज, न रोशनी, न भीड़ज आखिरकार हमने कर दिखाया। जस्ट मेरिड। इस पोस्ट से उन्होंने अपनी शादी की खबर सबको दी। खास बात यह रही कि उन्होंने दूल्हे का चेहरा उजागर नहीं किया और समारोह में सिर्फ करीबी लोगों की मौजूदगी रही।

दूल्हे की पहचान पर रहस्य

हालांकि ग्रेस ने अपने पति का नाम या चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री में यह चर्चा है कि उन्होंने संगीत निर्देशक एबी के साथ सात फेरे लिए हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद, ग्रेस को शुभकामनाएं देने वालों में इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल रहे।

अभिनेत्री का फिल्मी सफर

ग्रेस एंटनी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे किरदारों से की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली कुंबलंगी नाइट्स से, जिसमें उन्होंने फहद फासिल की पत्नी का रोल निभाया था। इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात लोकप्रियता दिलाई। हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी सीरीज नागेंद्रन'स हनीमून में भी उनके अभिनय की काफी चर्चा हुई थी।

अचानक हुई शादी से हैरान फैंस

ग्रेस की शादी की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई घोषणा नहीं की थी। यही वजह है कि जब तस्वीरें सामने आईं तो सोशल मीडिया पर यह खबर तुरंत वायरल हो गई।

मैंने कभी भी सेफ चॉइस नहीं की वह मेरे डीएनए में ही नहीं

हेट स्टोरी 2 जैसी बोल्ड फिल्म से डेब्यू करने वाली सुरवीन चावला ने अग्ली, पार्च्ड, सेक्रेड गेम्स जैसी लीक से हटकर फिल्में और सीरीज करके बतौर ऐक्टर अपनी अलग जगह बनाई है। इस साल चार वेब शोज क्रिमिनल जस्टिस 4, मंडला मर्डर्स, राणा नायडू 2 और अंधेरा में नजर आई सुरवीन से विविध पहलुओं पर की खास बातचीत।

आपने हेट स्टोरी 2, पार्च्ड से लेकर सेक्रेड गेम्स और हालिया शो अंधेरा तक में हमेशा बोल्ड और लीक से हटकर किरदार चुने हैं। क्या पैमाना रहता है आपका किरदार चुनने का?

मेरे पास आते ही ऐसे आड़े-टेढ़े रोल हैं, वरना मेरा सिंपल, नाच-गाने वाला हल्का-फुल्का काम करने का बहुत मन करता है। वो जो हार्ड कोर कमर्शल फिल्में होती हैं ना, वो मेरा फेवरिट है। मैंने पंजाबी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं ऐसी मेनस्ट्रीम नाच-गाने वाली लव स्टोरी फिल्में की भी बहुत हैं, मगर अभी कॉन्टेंट थोड़ा अलग हो गया है। डार्क कॉन्टेंट ज्यादा बन रहा है, पर मैं बतौर दर्शक हल्का-फुल्का कॉन्टेंट देखना भी चाहूंगी और उसका हिस्सा भी बनना चाहूंगी। मेरा मानना है कि आप शुरू में जैसा काम करते हैं, वैसा ही आगे मिलता है और मैंने कभी भी सेफ चॉइस नहीं की। वह मेरे डीएनए में ही नहीं है। मैं यह सोचकर हां नहीं करती कि यह रिस्की है तो करना चाहिए। आज मेरे लिए काम, परिवार के साथ मेरा बच्चा भी मेरी प्राथमिकता है, तो मैं वो काम करना चाहूंगी, जिसे करके वही खुशी मिले, जो एक लंबे दिन के बाद मुझे अपने बच्चे को देखकर मिलती है। उस काम को लेकर मेरी आंखों में वही उत्साह और चमक होनी चाहिए।

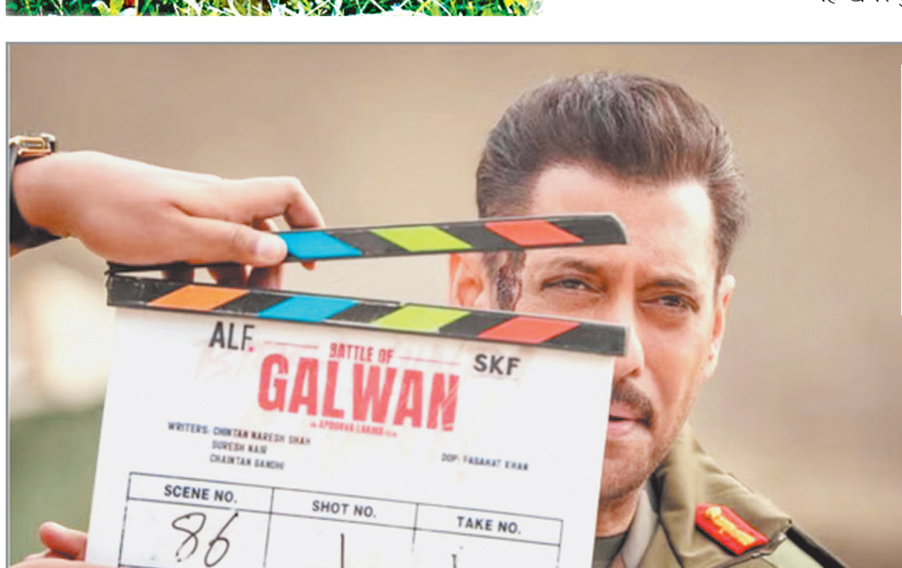

माथे से गिरता खून और शरीर पर वर्दी

'बैटल ऑफ गलवां' शूटिंग सेट से सलमान ने शेयर की तस्वीर

सलमान खान ने अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवां' की शूटिंग सेट से एक तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर छा गई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवां' की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर बैटल ऑफ गलवां सेट से एक तस्वीर साझा की है, जो इंटरनेट पर आते ही छा गई है। नेटिजंस इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

शूटिंग सेट पर दिखे अभिनेता

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवां की शूटिंग करते दिख रहे हैं। साझा की गई तस्वीर में अभिनेता के माथे से खून बहता दिख रहा है और वो वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। साथ ही सलमान के सामने एक्शन के लिए क्लैपबोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिपः

निखत 5-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली, एजेंसी। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने मंगलवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 51 किग्रा वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जापान की युमा निशिनाका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत के अलावा मीनाक्षी, जदुमणि और अभिनाश जामवाल भी क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। निखत का इस साल का पहला इवेंट 29 साल निखत के लिए यह इस साल का पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। पहले राउंड में जापानी खिलाड़ी ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन निखत ने अपनी लय बनाए रखी और जीत हासिल की। मैच के दौरान युमा ने निखत के रिदम को तोड़ने के लिए अत्यधिक क्लिंचिंग (गले लगाकर रुकने) की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें दो पेनल्टी पॉइंट्स का नुकसान हुआ। निखत ने जापानी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और सर्वसम्मति से जीत हासिल की। 48 KG में मीनाक्षी ने चीनी खिलाड़ी को हराया निखत के अलावा अन्य भारतीय बॉक्सरों ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मीनाक्षी (48 किग्रा) ने चीन की वांग क्यूपिंग को 5-0 से हराया। जबकि जदुमणि (57 किग्रा) ने इंग्लैंड की रीडशॉ रीस को 5-0 से पराजित किया। वहीं, अभिनाश जामवाल (65 किग्रा) ने डोमिनिकन गणराज्य के पीटर यनोआ फर्नांडो डी जीसस को 5-0 से मात देकर अगले दौर में जगह पक्की की।

आर्चरीः

विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन, भारतीय पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में पदक की दौड़ से बाहर

ग्वांगजू (दक्षिण कोरिया), एजेंसी। तीनों में सबसे अनुभवी ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा को सबसे कठिन ड्रॉ मिला, क्योंकि पहले दौर में उनका मुकाबला पूर्व ओलंपिक चैंपियन मेटे गाजोज से हुआ। भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजों का विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा और उसके सभी तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग के पदक चरण में जगह बनाने में असफल रहे।भारत के तीनों खिलाड़ियों में राहुल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे राउंड (अंतिम-32) में जगह बनाई, लेकिन शूट-ऑफ में जॉर्जिया के एलेक्जेंडर माचावरियानी से 5-6 (8-10) से हार गए। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने 5-3 की बढ़त बना ली थी, लेकिन अंतिम दो सेटों में वह लड़खड़ा गए, जिससे एक बार फिर रिकर्व वर्ग में दबाव में भारत की मानसिक कमजोरियां उजागर हो गईं। पहला सेट 28-28 से बराबर करने के बाद राहुल ने दूसरे सेट में 30-30 का शानदार स्कोर बनाया और तीसरे सेट में 28-27 से जीत हासिल कर 5-1 की बढ़त बना ली।

चौथे राउंड में उन्हें केवल ड्रॉ की आवश्यकता थी, लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे उनके विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का मौका मिल गया। जॉर्जियाई खिलाड़ी ने पांचवां सेट 28-27 से जीतकर शूट-ऑफ कराया, जहां राहुल ने आठ अंक हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी का स्कोर परफेक्ट 10 था। तीनों में सबसे अनुभवी ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा को सबसे कठिन ड्रॉ मिला, क्योंकि पहले दौर में उनका मुकाबला पूर्व ओलंपिक चैंपियन मेटे गाजोज से हुआ। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को पहला सेट 29-29 से बराबर करने के बाद 2-6 से हार का सामना करना पड़ा।

दूसरे सेट में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन गाजोज़ के दो 10 ने उन्हें 29-28 की बढ़त दिला दी। तुर्किए के तीरंदाज ने तीसरे सेट में 29-28 के साथ अपनी बढ़त 5-2 कर ली। धीरज ने चौथा सेट 29-29 से बराबर किया, लेकिन यह गाजोज को जीत से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। भारत के एक अन्य खिलाड़ी नीरज चौहान को उज्बेकिस्तान के बोबराजाबोव बेकजोद से सीधे सेटों में 27-29, 27-28, 26-29 से हार का सामना करना पड़ा।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल

➤ पाकिस्तान कर सकता है खेल खराब

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 2026 का पुरुष टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। भारत अपना खिताब बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिसने पिछली बार 2024 में बारबाडोस में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था।

इस टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेंगी और 55 मैच खेले जाएंगे। मैच भारत में 5 और श्रीलंका में दो स्थानों पर खेले जाएंगे तथा फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता है, तो यह मैच कोलंबो में होगा।

बीसीसीआई टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। हालांकि इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था कि वे दोनों सरकारों के बीच लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण एक-दूसरे के देशों में नहीं खेलेंगे जिसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान के सभी मैचों के आयोजन के लिए सह-मेजबान चुना गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आईसीसी ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए समय निश्चित रूप से तय कर लिया गया है और सभी भाग लेने वाले देशों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

फिलहाल अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए केवल 15 टीमें ही क्वालीफाई कर पाई हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और पहली बार इटली भी शामिल हैं। शेष पांच स्थानों में से दो अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर से और तीन एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर से निकलेंगे।

अफगानिस्तान का विजयी आगाज, एशिया कप के पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को धोया

नई दिल्ली, एजेंसी। एशिया कप के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को 94 रनों से करारी शिकस्त दी है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने उमरजई और अटल की शानदार फिफ्टी के दम पर 189 रनों का लक्ष्य हॉन्ग कॉन्ग के सामने रखा था. इसके जवाब में उतरी हॉन्ग कॉन्ग की टीम 94 रन ही बना सकी.

ऐसी रही हॉन्ग कॉन्ग की पारीः 189 के जवाब में उतरी हॉन्ग कॉन्ग की शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही ओवर में फारुकी ने अंशुमान रथ का विकेट झटका. अंशुमान अपना खाता भी नहीं खोल सके. इसके बाद दूसरे ओवर में हॉन्ग कॉन्ग को एक और झटका लगा जब उमरजई ने जीशान अली का विकेट झटका. इसके बाद तीसरे ओवर में 13 के स्कोर पर भी हॉन्ग कॉन्ग को झटका लगा और निजाकत रन आउट हो गए. पांचवे ओवर में भी हॉन्ग कॉन्ग को झटका लगा. इसके बाद 10वें ओवर में भी हॉन्ग कॉन्ग को झटका लगा जब किंचित शाह 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद अच्छी लय में दिख रहे बाबर हयात का भी विकेट गिर गया. इसके बाद हॉन्ग कॉन्ग की पारी और लड़खड़ा गई और टीम 20 ओवर खेलकर 9 विकेट गंवाने के बाद केवल 94 रन ही बना सकी. अफगानिस्तान ने 94 रनों से ये मैच जीत लिया.

ऐसी रही अफगानिस्तान की पारीः अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. पारी का आगाज अटल और गुरबाज ने किया. लेकिन तीसरे ही ओवर में अफगानिस्तान को पहला झटका लगा जब गुरबाज 8 रन बनाकर आयुष शुक्ला का शिकार बन गए. इसके बाद चौथे ओवर में इब्राहिम जादरान भी 1 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन फिर नबी और अटल के बीच अच्छी साझेदारी हुई. टीम को तीसरा झटका 77 के स्कोर पर 11वें ओवर में लगा. नबी 33 रन बनाकर किंचित का शिकार बने. फिर नाइब का विकेट 13वें ओवर में गिरा. नाइब 5 रन बना सके. लेकिन अटल को साथ मिला अजमतुल्लाह उमरजई का जिन्होंने शानदार फिफ्टी लगाई. उमरजई ने 53 रन बनाए. दोनों की इस पारी के दम पर अफगानिस्तान ने 188 रन बनाए.

फीफा वर्ल्ड कपः बोलीविया ने ब्राजील को हराया, क्वालिफाइंग प्लेऑफ में प्रवेश किया

एल आल्टो (बोलीविया), एजेंसी। बोलीविया का लक्ष्य चौथी बार तथा 1994 के बाद पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना होगा। मिगुएल टेरसेरोस ने पहले हाफ में पेनल्टी पर गोल किया जिससे बोलीविया ने मंगलवार को विश्व का फुटबॉल के दक्षिण अमेरिकी क्वालिफाइंग में ब्राजील को 1-0 से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित की। टेरसेरोस ने 45वें मिनट में गोल करके बोलिवियाई टीम को 2019 के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर ब्राजील पर जीत दिलाई।

प्लेऑफ टूर्नामेंट में छह देश शामिल होंगे और यह मार्च के अंतरराष्ट्रीय सत्र में खेला जाएगा, जिससे अगले वर्ष अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप के लिए अंतिम दो स्थानों का निर्धारण होगा। बोलीविया का लक्ष्य चौथी बार तथा 1994 के बाद पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफायर में तीसरे स्थान पर रहने वाली कोलंबियाई टीम ने स्ट्राइकर लुइस डियाज के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेनेजुएला को 6-3 से हराकर बोलीविया की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में मदद की। डियाज ने चार गोल दागे। क्वालिफाइंग के एक अन्य मैच मे इक्काडोर ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया।

एशेज सीरीज की तैयारी में जुटे कमिंस, चोट से वापसी के लिए समयसीमा तय की

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित करना चाहते हैं, उन्होंने बॉलिंग क्रीज पर वापसी के लिए समयसीमा तय की है। जुलाई में कैरेबियन दौरे में खेलने के बाद से पैट कमिंस कमर दर्द से जूझ रहे हैं।

उनकी हालिया स्कैन रिपोर्ट में प्रभावित हिस्से में लंबर बोन स्ट्रेस की पुष्टि हुई है। कमिंस को आराम की जरूरत है, लेकिन दौड़ने या गेंदबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जानते हैं कि उन्हें एशेज सीरीज से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 21 नवंबर से होगी। कमिंस को उम्मीद है कि एशेज की शुरुआत से लगभग चार से छह हफ्ते पहले वह दोबारा गेंदबाजी शुरू कर पाएंगे। कमिंस ने बुधवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में कहा, मैं कम से कम एक महीने पहले, शायद छह हफ्ते पहले गेंदबाजी करना शुरू करना चाहूंगा, लेकिन मैंने इस पर अभी ज्यादा नहीं सोचा है। अभी भी इंतजार करना होगा और देखना होगा। हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए जब चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी नजदीक होगी, तो वापसी का रोडमैप तय करेंगे। अगर पैट कमिंस को शुरुआती टेस्ट से बाहर होना पड़ा, तो ऐसे में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड उनकी जगह ले सकते हैं। अनुभवी तिकड़ी मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन का खेलना लगभग तय है। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल अगले कुछ हफ्तों तक ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग नहीं करूंगा। मुझे ज्यादा दौड़ना नहीं है और गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करनी।

21-25 नवंबर के बीच पर्थ में एशेज सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 4-8 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में दूसरा मुकाबला आयोजित होगा। 17-21 दिसंबर के बीच दोनों टीमें एडिलेड में तीसरे टेस्ट के लिए भिड़ेंगी, जबकि 26-30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में चौथा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच का आयोजन अगले साल 4-8 जनवरी के बीच सिडनी में होगा।

इन्फ्लुएंसर विवाद केसः कोर्ट ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर लगाया 100 रुपए जुर्माना

मुंबई, एजेंसी। डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के खिलाफ कथित मारपीट के मामले में जवाब देने में देरी के चलते भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। सपना गिल के वकील अली काशिफ खान का मानना है कि यह कोर्ट की ओर से दिया गया एक बड़ा संदेश है। वकील अली काशिफ खान ने कहा, हमने अपनी क्लाइंट

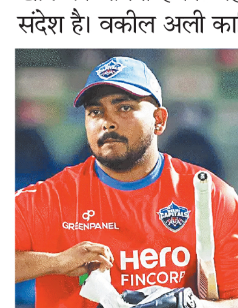

के साथ हाथापाई को लेकर पृथ्वी शॉ और उनके ग्रुप के खिलाफ शिकायत की थी। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो हमने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर मांग की थी कि वह एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दें, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को सिर्फ पूछताछ का ऑर्डर दिया। ऐसे में हमने सेशंस कोर्ट डिंडोशी में ऑर्डर को चैलेंज किया। आज करीब एक साल का समय बीच चुका है, लेकिन इस मामले में पृथ्वी शॉ का कोई जवाब नहीं आया है।

उन्होंने कहा, सेशंस कोर्ट डिंडोशी के जज ने पृथ्वी शॉ को कई बार जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इसके बाद से उनके वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से ज्यादा डेट्स ले ली हैं। बुधवार को जब उनके वकील से जवाब दाखिल करने को कहा गया, तो उन्होंने फिर से वक्त मांगा, जिसे सुनते ही जज ने 100 रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया।

गावस्कर ने ब्रोंको टेस्ट को कहा अनुचित, सभी के लिए एक ही मानक रखना लगभग असंभव

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुष टीम में खिलाड़ियों के चयन के लिए ब्रोंको टेस्ट शुरू करने की योजना ने सभी का ध्यान खींचा है। यह एक ऐसा टेस्ट है जो एथलीटों को अपनी हृदय संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रोंको टेस्ट क्रिकेट के लिए भले ही नया हो, लेकिन रग्बी में इसका इस्तेमाल लंबे समय से एक उच्च-तीव्रता वाली दौड़ के अभ्यास के रूप में किया जाता रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इसके खिलाफअपने विचार साझा करते हुए कहा कि इस तरह के टेस्ट के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करना काफी अनुचित है। गावस्कर ने अपने एक कॉलम में लिखा, हालांकि यह जानने के लिए कि किसी खिलाड़ी को अपने शरीर को कहां मजबूत करने की जरूरत है, ये टेस्ट करवाना ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय टीम में चयन का फैसला इनसे करवाना थोड़ा ज़्यादा है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए टीम में सभी के लिए एक ही मानक रखना लगभग असंभव है।

महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित

नई दिल्ली, एजेंसी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कमान सोफी डिवाइन के पास है। 22 वर्षीय ऑलराउंडर फ्लोरा डेवोनशायर को घरेलू स्तर पर प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में शामिल किया गया है। पिछले संस्करण की मेजबानी के बाद से न्यूजीलैंड टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बार न्यूजीलैंड ने अपने खेमे में छह ऐसी खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएंगी। इसके अलावा, चार खिलाड़ी ऐसी भी होंगी, जो अपने पहले सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।

न्यूजीलैंड की टीमः सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इजी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोजमैरी मेयर, जॉर्जिया प्लिम्मर और ली ताहुहु।

सोफी डिवाइन अपना पांचवां वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। उनकी साथी सूजी बेट्स भी अपने पांचवें वनडे विश्व कप में खेल रही हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज ली ताहुहू को चौथे विश्व कप में खेलने का मौका मिला है, जबकि मैडी ग्रीन और मेली केर अपने तीसरे विश्व कप में भाग ले रही हैं।

30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का पहला मैच 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इसके बाद न्यूजीलैंड 6 अक्टूबर को साउथ अफ्रीकी टीम से भिड़ेगी। 10 अक्टूबर को उसका सामना बांग्लादेश से होगा। न्यूजीलैंड की टीम 14 अक्टूबर को श्रीलंका से भिड़ेगी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। यह टीम 23 अक्टूबर को भारतीय टीम को चुनौती देगी, जबकि 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से होगा।

न्यूजीलैंड के कोच बेन सॉयर ने टीम में चुने गए सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं टीम के संतुलन से वास्तव में खुश हूं। मुझे लगता है कि परिस्थितियों और विरोधियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास सही मिश्रण है, जिससे हम उन सभी चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, जिनका हम सामना करेंगे।

महाराष्ट्र सरकार को आदेश: अकोला दंगों की SIT में दोनों समुदायों के अफसर शामिल हों

-धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट का संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाएगा, जब उसकी न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष रहे। पुलिस तंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अक्सर साम्प्रदायिक या जातिगत पूर्वाग्रहों के आरोप लगते रहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के 2023 अकोला दंगों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि "वर्दी पहनने के बाद पुलिस अधिकारी की पहचान केवल कानून का रक्षक होना चाहिए, न कि उसकी जाति या धर्म।"

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गुरुवार को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच 17 वर्षीय मोहम्मद शरीफ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि अकोला दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए। इस SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अफसर शामिल किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि केवल तभी लोगों में भरोसा बनेगा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी पुलिसकर्मी को अपने धर्म या जाति की पहचान से ऊपर उठकर काम करना होगा, क्योंकि वर्दी पहनते ही वह केवल "कानून का सेवक" बन जाता है।

अकोला दंगों की पृष्ठभूमि

अकोला, विदर्भ क्षेत्र का एक संवेदनशील जिला, मई 2023 में अचानक हिंसा की आग में झुलस गया। 13 मई 2023 को घटना: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर शहर के ओल्ड सिटी इलाके में दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और कुछ ने थाने का घेराव करने की भी कोशिश की।

हिंसा का परिणाम: इस दंगे में विलास महादेवरो गायकवाड़ नामक व्यक्ति की मौत हो गई। दो पुलिसकर्मियों समेत कुल आठ लोग घायल हुए। शहर में लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही और प्रशासन को कर्फ्यू जैसे हालात बनाने पड़े।

पुलिस पर उठे सवाल

दंगों के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कुछ पक्षों का आरोप था कि कार्रवाई एकतरफा की गई, वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि पुलिस पूरी तरह लाचार नजर आई। इसी संदर्भ में मोहम्मद शरीफ नामक 17 वर्षीय युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसका तर्क था कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब दोनों समुदायों के अधिकारी SIT का हिस्सा हों।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का महत्व

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ अकोला दंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की कानून-व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक है। धर्मनिरपेक्षता का संदेश – पुलिस लोकतंत्र का प्रहरी है और उसका काम धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर कानून लागू करना है। जनता का भरोसा कायम करना – जब लोगों को लगेगा कि जांच में दोनों समुदायों के अधिकारी शामिल हैं, तो न सिर्फ निष्पक्षता होगी बल्कि निष्पक्षता दिखाई भी देगी। भविष्य के लिए सीख – भारत जैसे विविधता वाले देश में दंगों के समय सबसे बड़ा संकट भरोसे का होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पुलिस प्रशासन के लिए भविष्य की दिशा तय करेगा।

महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी

अब महाराष्ट्र सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन करे। SIT का गठन जल्दी किया जाए और उसमें निष्पक्ष तथा अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति हो। जांच केवल दोषियों को सज़ा दिलाने तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव भी दे। दंगे में मारे गए और घायल लोगों के परिवारों को न्याय और मुआवजा दिया जाए।

साम्प्रदायिक हिंसा और भारतीय समाज

अकोला दंगा कोई पहला मामला नहीं है। भारत के कई हिस्सों में सोशल मीडिया पोस्ट या छोटी-सी अफवाह भी बड़े दंगों का रूप ले लेती है। इसके पीछे सामाजिक अविश्वास, राजनीतिक स्वार्थ और अफवाह फैलाने वाली ताकतें जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अगर पुलिस निष्पक्ष और सख्ती से काम करे तो दंगाई ताकतें हिम्मत नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल अकोला दंगे के पीड़ितों के लिए राहत है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि "पुलिसकर्मी की पहचान उसकी वर्दी से होनी चाहिए, न कि धर्म या जाति से।" महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली SIT पर अब सबकी निगाहें होंगी। उम्मीद है कि यह कदम न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाएगा, बल्कि भविष्य में प्रशासन और पुलिस को यह याद दिलाएगा कि उनका असली धर्म केवल कानून और संविधान है।

नेपाल में फंसे भारतीयों की आपबीती: दहशत, भूख और मौत का डर

-एयरपोर्ट बना कैदखाना: तीन दिन से बंद यात्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक संकट और हिंसा की आग में झुलस रहा है। 8 सितंबर से शुरू हुई हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ नेपाल की सड़कों को असुरक्षित बना दिया है, बल्कि वहां फंसे सैकड़ों भारतीयों की जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। जिन भारतीयों ने कभी नेपाल की यात्रा को पर्यटन, इलाज या धार्मिक उद्देश्यों से किया था, आज वही लोग खुद को एक कैदखाने जैसी स्थिति में पा रहे हैं। हवाई अड्डों पर तीन-तीन दिन से फंसे लोग बताते हैं कि न सिर्फ बाहर निकलना मुश्किल है बल्कि खाने-पीने तक के लाले पड़ गए हैं।

हवाई अड्डा बना बंदीगृह

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय परिवार फंसे हुए हैं। यहां कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। इन लोगों का कहना है कि वे तीन दिन से एयरपोर्ट के भीतर कैद जैसे हालात में हैं। हर तरफ से फायरिंग और धुआं उठने की खबरें आती रहती हैं, जिससे बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे। खाने-पीने की वस्तुएं धीरे-धीरे खत्म हो चुकी हैं। कई परिवार तो भूख की कगार पर पहुंच गए हैं।

गुजरात के सैकड़ों लोग मुश्किल में

सबसे ज्यादा परेशानी गुजरात से गए पर्यटकों और मरीजों को हो रही है। जानकारी के अनुसार, केवल गुजरात से ही 300 से ज्यादा लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। इनमें राजकोट के करीब 43 लोग, अहमदाबाद के 9 और राजकोट जिले से ही 50 से 55 अन्य लोग शामिल हैं। इन सभी ने मजबूरी में स्थानीय होटलों, धर्मशालाओं और यहां तक कि वृद्धाश्रमों में भी पनाह ली है।

देवांगभाई चोकसी और उनका परिवार

इन फंसे हुए लोगों में सूरत नेशनल बैंक के डायरेक्टर देवांगभाई चोकसी और उनका परिवार भी शामिल है। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए सूरत के सांसद मुकेश दलाल से अपनी आपबीती सुनाई। देवांगभाई के अनुसार, 10 सितंबर तक हालात बेहद भयावह रहे। चारों ओर आगजनी, हिंसा और गोलीबारी का माहौल था। जिस होटल में वे ठहरे हुए थे, वहां तक बिजली काट दी गई थी। रातभर अंधेरे में परिवार के साथ बैठना पड़ा। उन्होंने बताया कि हर पल ऐसा लगता है जैसे जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हों।

बस पर भी हमला, पत्थरबाजी से घायल

कुछ भारतीयों ने घर लौटने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ते में हिंसक भीड़ का सामना करना पड़ा। कई बसों पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें यात्रियों को चोटें भी आईं। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय लोगों ने सलाह दी कि वे बाहर न निकलें, वरना जान का खतरा हो सकता है।

बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान

इन भयावह हालातों में सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे बच्चों और महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। बच्चों के लिए दूध और बुनियादी जरूरतों की चीजें मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। कई परिवार दवाइयों की कमी से भी परेशान हैं, खासकर वे लोग जो इलाज करवाने नेपाल आए थे। जिन मरीजों को नियमित दवाएं लेनी होती हैं, उनके लिए स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी है।

भारतीय दूतावास और सरकार से उम्मीदें

नेपाल में फंसे भारतीय लगातार भारत सरकार और दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो और संदेश भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौटना चाहते हैं। भारत सरकार ने भी नेपाल में हालात पर नजर रखी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा और कर्फ्यू की वजह से राहत अभियान चलाना बेहद कठिन साबित हो रहा है।

मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष

देवांगभाई चोकसी की आपबीती हो या अन्य यात्रियों की कहानी, सबमें एक समानता है—हर कोई जिंदगी के लिए जूझ रहा है। एक तरफ लगातार गोलीबारी और आगजनी की खबरें, दूसरी तरफ खाने-पीने की कमी और बिजली का न होना, लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से भारी पड़ रहा है।

न खत्म होने वाला इंतजार

तीन दिन से एयरपोर्ट और स्थानीय होटलों में बंद भारतीय अब सिर्फ एक ही आस लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल ले। परिवारजन लगातार अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगह नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। नेपाल की मौजूदा स्थिति ने वहां मौजूद भारतीयों को भय और असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दिया है। हर तरफ अनिश्चितता और दहशत का माहौल है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सभी भूख और डर से बेहाल हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नेपाल जैसी नजदीकी और सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे।

आईफोन 17 सीरीज लॉन्च : क्या है नया और खास?

-सबसे पतला आईफोन एयर: डिज़ाइन और कीमत

नई दिल्ली। एपल ने 9 सितंबर को अपना सालाना टेक इवेंट आयोजित किया, जिसमें कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज को पेश किया। इस बार कंपनी ने यूज़र्स के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। सबसे खास बात यह रही कि प्लस वेरिएंट की जगह एपल ने अब तक का सबसे पतला आईफोन 'आईफोन एयर' लॉन्च किया, जिसकी डिजाइन को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए रखी गई है और टॉप मॉडल 1,59,900 रुपए तक जाता है।

डिस्प्ले और ब्राइटनेस में बड़ा सुधार

आईफोन 17 सीरीज के डिस्प्ले को लेकर कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है। इस बार सभी मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव और भी स्मूद हो जाता है। इसके अलावा फोन की स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक पहुंचाई गई है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले बेहद क्लियर दिखाई देगा। यह फीचर एंड्रॉइड के कई प्रीमियम फोन्स को टक्कर देगा।

ओवरहीटिंग रोकने के लिए नया कूलिंग सिस्टम

पिछली सीरीज में आईफोन 16 के प्रो मॉडल्स को लेकर यूज़र्स ने ओवरहीटिंग की शिकायत की थी। इस बार एपल ने खास ध्यान देते हुए प्रो मॉडल्स में वेपर कूलिंग चैंबर जोड़ा है। इससे फोन लंबे समय तक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी टास्क्स के दौरान भी गरम नहीं होगा।

कैमरा हुआ और भी पावरफुल

आईफोन 17 सीरीज का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका नया 18MP फ्रंट कैमरा है। पहले के मॉडल्स में 12MP का ही सेल्फी कैमरा दिया गया था। यानी अब यूज़र्स को वीडियो कॉलिंग, व्लॉगिंग और सेल्फी के लिए और बेहतर क्वालिटी मिलेगी। रियर कैमरा में भी प्रो मॉडल्स में एडवांस सेंसर और नाइट मोड परफॉर्मेंस को और अपग्रेड किया गया है।

बेस वैरिएंट की कीमत और स्टोरेज

आईफोन 17 का बेस वैरिएंट 82,900 रुपए से शुरू होता है। यह आईफोन 16 की तुलना में करीब 13,000 रुपए महंगा है। हालांकि, एपल ने इसकी कीमत को लेकर यूज़र्स की नाराज़गी से बचने के लिए स्टोरेज क्षमता को बढ़ा दिया है। जहां आईफोन 16 के बेस मॉडल में सिर्फ 128GB स्टोरेज मिलता था, वहीं आईफोन 17 का बेस मॉडल अब 256GB स्टोरेज के साथ आता है।

आईफोन 16 अब सस्ता, लेकिन स्टोरेज कम

नए लॉन्च के बाद एपल ने आईफोन 16 की कीमतों में कटौती कर दी है। अब यह 13 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 128GB ही स्टोरेज है, जबकि आज के दौर में ज्यादा ऐप्स और हाई-क्वालिटी वीडियो की वजह से स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है। ऐसे में लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आईफोन 17 बेहतर साबित हो सकता है।

डिजाइन और परफॉर्मेंस

आईफोन एयर ने इस बार सबका ध्यान खींचा है क्योंकि इसे एपल ने अब तक का सबसे पतला आईफोन बताया है। इसका डिजाइन बेहद स्लीक है और हाथ में पकड़ने में हल्का महसूस होता है।

काठमांडू में तीसरे दिन कर्फ्यू, सुशीला कार्की बनेंगी अंतरिम प्रधानमंत्री

-हिंसा में अब तक 31 मौतें और 1000 से ज्यादा घायल

काठमांडू (एजेंसी) । नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में लगातार तीन दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। यह कर्फ्यू सेना ने एहतियातन लगाया है ताकि हिंसा और अराजकता पर नियंत्रण रखा जा सके। हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन गुरुवार सुबह से सेना और Gen-Z आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। इस संकट ने नेपाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां अब सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।

हिंसा और जनहानि

पिछले तीन दिनों में भड़की हिंसा ने नेपाल को झकझोर दिया है। अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं। आम नागरिक सड़कों पर उतरकर सरकार और व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा युवा पीढ़ी यानी Gen-Z का था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सड़कों पर हिंसक रूप ले चुका है। काठमांडू की गलियों में सेना की गश्त, जगह-जगह बैरिकेड्स और कर्फ्यू का सन्नाटा—यह तस्वीर बताती है कि नेपाल की राजधानी कितनी अस्थिर स्थिति में है। अस्पतालों में घायल लोगों की लंबी कतारें हैं, वहीं दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

आर्मी और Gen-Z के बीच बातचीत

गुरुवार सुबह 10:30 बजे सेना मुख्यालय में Gen-Z प्रतिनिधियों और आर्मी अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। बुधवार को हुई पहली बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका था। सेना का कहना है कि वह हर पार्टी और नेता से राय ले रही है ताकि जल्द से जल्द एक स्वीकार्य अंतरिम सरकार बनाई जा सके। सेना को भी इस बात का एहसास है कि अगर राजनीतिक हल नहीं निकाला गया तो हिंसा और बढ़ सकती है। यही वजह है कि वह Gen-Z के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यह पहली बार है जब नेपाल में एक आंदोलनकारी युवा समूह सीधे सेना और राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत की स्थिति में आया है।

सुशीला कार्की पर आम सहमति

नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकीं सुशीला कार्की का नाम अब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। उन्हें न केवल सेना का बल्कि Gen-Z आंदोलनकारियों और काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालेन शाह का भी समर्थन प्राप्त है। सुशीला कार्की को एक "स्वीकार्य चेहरा" मानकर आगे लाया गया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि वे बालेन शाह की प्रॉक्सी के रूप में काम करेंगी। बालेन वर्तमान में युवा वर्ग में बेहद लोकप्रिय हैं और माना जा रहा है कि जब भी नेपाल में चुनाव होंगे, वह खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इस बीच, कार्की का कार्यकाल अंतरिम सरकार को संभालने और चुनाव की तैयारी कराने तक सीमित रहेगा।

सुशीला कार्की का करियर और छवि

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपने साहसिक और स्वतंत्र फैसलों के लिए जानी गईं। उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की कोशिश की। उनकी छवि एक सख्त, ईमानदार और निष्पक्ष नेता की है। यही कारण है कि मौजूदा हालात में वे सेना, आंदोलनकारी और आम जनता तीनों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी हैं।

राजनीतिक भविष्य की तस्वीर

अगर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी— देश में शांति और स्थिरता बहाल करना, हिंसा से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य करना, और सबसे अहम, निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करना। नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है।

ट्रम्प समर्थक चार्ली कर्क की हत्या: यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गोलीबारी, अमेरिका में शोक की लहर

-शोक में 4 दिन अमेरिकी झंडा झुकाया

यूटा (एजेंसी)। अमेरिका में राजनीतिक तनाव और हिंसा की एक और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है। यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली कर्क उस समय 'द अमेरिकन कमबैक टूर' नामक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यह घटना न सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सदमा देने वाली रही। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि चार्ली कर्क एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर छात्रों और अन्य उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। अचानक ही उनके गर्दन के पास गोली लग गई। इस गोलीबारी के कारण भारी मात्रा में रक्त बहा और चार्ली जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मी तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका। चार्ली कर्क अमेरिकी राजनीति में एक जानी-मानी हस्ती थे। वह 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' (TPUSA) नामक संस्था के प्रमुख थे। इस संस्था का उद्देश्य मुख्यतः स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को राजनीति, नागरिक जिम्मेदारी और देशभक्ति की जानकारी देना था। वह ट्रम्प के कट्टर समर्थक माने जाते थे और अक्सर राजनीतिक रैलियों और विश्वविद्यालय कार्यक्रमों में अपने विचार साझा करते रहते थे। उनकी गतिविधियाँ और विचार अमेरिकी दाएं राजनीतिक धड़े के बीच काफी प्रभावशाली माने जाते थे। घटना के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे परिसर में छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और फेडरल एजेंसियों ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन था और उसने यह हत्या क्यों की। प्रारंभिक जांच में यह माना जा रहा है कि यह राजनीतिक या व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम हो सकता है, लेकिन पुलिस ने कोई निश्चित बयान नहीं दिया है। चार्ली कर्क की हत्या ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा पर बहस को और तीव्र कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा की घटनाएँ बढ़ी हैं। ट्रम्प समर्थक और विरोधी समूहों के बीच तनाव अक्सर भड़क जाता है, और इस तरह की घटनाएँ इसे और गहरा कर देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद और समझ की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग हिंसा को माध्यम मानकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चार्ली कर्क की मृत्यु के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह घटना उनके लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर दुखद है। उनके आदेशानुसार चार दिन के लिए अमेरिकी झंडा आधा झुका दिया गया। ट्रम्प समर्थकों और TPUSA के सदस्यों ने भी सोशल मीडिया पर चार्ली के लिए श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए। चार्ली कर्क का योगदान केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं था। वह छात्रों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए काम करते थे। उनके कार्यक्रमों में अक्सर युवा सक्रिय रूप से भाग लेते थे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। TPUSA के माध्यम से उन्होंने कई युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उनके समर्थक उन्हें एक मार्गदर्शक और नेता के रूप में देखते थे। हालांकि, इस घटना ने यह सवाल भी उठाया है कि अमेरिका में राजनीतिक सुरक्षा और सुरक्षा इंतजाम कितने मजबूत हैं। विश्वविद्यालय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर राजनीतिक विचार रखने वाले वक्ताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर बहस होती रहती है। इस घटना के बाद कई विश्वविद्यालयों ने अपनी सुरक्षा नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। चार्ली कर्क की हत्या का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। यह घटना अमेरिकी समाज के लिए भी चेतावनी है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा का स्तर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज में संवाद और सहिष्णुता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं से न केवल राजनीतिक जीवन बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इस समय पुलिस और एफबीआई मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई भी अटकलें या अफवाहें फैलाने से बचें और जांच में सहयोग करें।

बुजुर्ग नेताओं से तंग आए युवा: संसद भंग

-लेकिन संविधान सुरक्षित- नेपाल का नया आंदोलन

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के दौर से गुजर रही है। संसद भंग होने और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। इस बीच, नेपाल की नई पीढ़ी—Gen-Z—के नेता पहली बार खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अपने आंदोलन की वजह और मकसद दोनों को स्पष्ट करने की कोशिश की है।

बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया आंदोलन

Gen-Z नेताओं अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने साफ कहा कि यह आंदोलन संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि संसद और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। अनिल बनिया ने कहा, "हमने शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी, लेकिन हिंसा और आगजनी उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने की जिनका उद्देश्य आंदोलन को बदनाम करना था।" उनका मानना है कि पिछले कई दशकों से सत्ता में बैठे बुजुर्ग नेताओं ने न तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया और न ही देश को स्थिरता दी। इसीलिए युवाओं ने मजबूरी में सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। दिवाकर दंगल ने यह स्वीकार किया कि अभी Gen-Z पूरी तरह परिपक्व नहीं है और नेतृत्व संभालने के लिए उन्हें समय चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ताकतें उन्हें तोड़ने और आपस में बांटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी एकजुट रहकर बदलाव की लड़ाई जारी रखेगी।

अंतरिम प्रधानमंत्री की तलाश

सबसे बड़ी चुनौती इस समय नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के चयन की है। बुधवार को हुए तख्तापलट के बाद आर्मी और Gen-Z नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है। गुरुवार सुबह खबर आई कि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और उनकी छवि ईमानदार व सख्त न्यायाधीश की रही है। लेकिन दोपहर तक हालात बदल गए। 'लाइट मैन' के नाम से मशहूर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कुलमान घीसिंग का नाम भी सामने आया। घीसिंग को नेपाल में बिजली संकट दूर करने के लिए जाना जाता है और युवाओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है। इस तरह अब तक अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है।

सेना और Gen-Z के बीच बातचीत

नेपाल आर्मी इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभा रही है। आर्मी मुख्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें Gen-Z नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। सेना का मकसद देश में शांति और स्थिरता बहाल करना है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अराजकता को बढ़ने नहीं देना चाहती। इसी वजह से राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा गया है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,